वर्ष 19
अंक 159
10 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार, 21 अगस्त 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल, **मुंबई** और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बी साईराम ⏩ पृष्ठ 4

राज्यों के हितों की रक्षा के लिए कोल इंडिया प्रतिबद्ध

शिनजिरो कोइजुमी व राजनाथ सिंह ⏩ पृष्ठ 10

भारत-जापान में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता

डॉलर रु. 95.70 ▼ 0.1 रु. | यूरो रु. 112.0 ▲ 0.9 रु. | सोना (10 ग्राम) रु. 1,56,451 ▲ 3,199 रु. | सेंसेक्स 77537.70 ▲ 628.0 | निफ्टी 24231.80 ▲ 153.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 24293.0 ▲ 61.20 | ब्रेंट क्रूड 92.60 ▲ 2.6 डॉलर

एक नज़र

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' जारी करते हुए कहा कि शहर में करीब 40 लाख नए मकान बनाए जाएंगे और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2047 तक मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार कर 695 किलोमीटर किया जाएगा। मनोहर लाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल टी. एस. संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली की आबादी बढ़कर 3.20 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे विकास पर दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यमुना के 180 वर्ग किलोमीटर बाढ़ क्षेत्र और रिज क्षेत्र का संरक्षण भी किया जाएगा। शहर में मेट्रो रेल, बसों और छह नए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) गलियारों समेत सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत किफायती आवास को बढ़ावा दिया जाएगा। पृष्ठ 4

कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात बगैर शुल्क करने की इजाजत दे दी गई है। भारत को करीब 10 साल के बाद चीनी आयात करना पड़ रहा है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक चीनी का आयात 31 अक्टूबर, 2026 तक ही किया जा सकेगा। इस तरह शुल्क मुक्त आयात के लिए दो महीने से कुछ ज्यादा वक्त मिलेगा, जब त्योहारों की वजह से देश में चीनी की सबसे ज्यादा खपत होती है। गन्ने की पेराई नवंबर से शुरू होती है। पृष्ठ 4

आज का सवाल

क्या सोशल मीडिया पर सामग्री की जांच में मानव दखल है जरूरी ?

www.bshindi.com पर राय भेजें।

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **Y** और यदि न है तो **N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या आयात से घटेंगे चीनी के दाम ?

हां	नहीं
75%	25%

व्यापार गोष्ठी

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर आपकी राय ?

अपनी राय पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाऊस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर – 011-23720201 या फिर ई-मेल करें **goshthi@bsmail.in**

अपने विचार आप हमें **www.bshindi.com पर भी भेज सकते हैं**

सामग्री जांच में मानव दखल कम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री हटाने वाली प्रणालियों में मानव समीक्षकों की कमी पर चिंता

आशिष आर्यन
नई दिल्ली, 20 अगस्त

सरकार ने मेटा के आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम यानी किसी सामग्री को पहचान कर हटाने वाली प्रणालियों में मानव समीक्षकों की मौजूदगी न होने पर चिंता जताई है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कंपनी से ऐसे सिस्टम स्थापित करने के लिए कहा है जो यह सुनिश्चित करे कि उपयोगकर्ताओं की सामग्री केवल एआई इंजन के निर्णयों के आधार पर न हटाई जाए।

हाल में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया। उसमें कंपनी के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल कैपलन भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ कंपनी के एआई सिस्टम को उसके तीन प्लेटफॉर्मों पर सामग्री चिह्नित करने और उन्हें हटाने के लिए केवल स्टैटिक कीवर्ड का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

बैठकों में मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि उस तरीके में समस्या थी। उसके जरिये किसी भी सामग्री को हटाया जा सकता था भले ही वह किसी कानून या सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करती हो। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'उदाहरण के लिए हाल में एक सरकारी संगठन ने बताया था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने किस प्रकार कुछ देशों से खालिस्तान समर्थक भगोड़ों का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण किया था। जब इस ऑपरेशन का विवरण उस सरकारी विभाग द्वारा फेसबुक पर साझा किया गया तो 'खालिस्तान समर्थक' शब्द की मौजूदगी के कारण एआई-एनेबल्ड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम ने उस पोस्ट के संदर्भ को समझे बिना खुद-ब-खुद उसे हटा दिया।' अधिकारी ने कहा कि अगर उसकी समीक्षा मानव द्वारा की जाती तो ऐसी गलती नहीं होती।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मेटा के अलावा एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी एआई के जरिये निर्णय लेने की प्रणाली में मानव एजेंट की कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम सामुदायिक मानकों के अनुसार प्रतिबंधित या वर्जित कीवर्ड वाली किसी भी पोस्ट तक पहुंच को प्रतिबंधित कर देते हैं।

अधिकारी ने कहा, 'फिलहाल हम उन मामलों का अध्ययन कर रहे हैं जहां सोशल मीडिया मध्यस्थों के एआई आधारित कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम द्वारा महज किसी खास शब्द के कारण पोस्ट को हटा दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं।'

इस मुद्दे पर जानकारी के लिए मेटा और आईटी मंत्रालय को भेजे गए ईमेल का खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया।

इस साल 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेटा के वरिष्ठ वैश्विक और भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) एवं अन्य सामग्री से निपटने के कंपनी के तरीके पर सवाल उठाए। बैठक में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कपलान भी शामिल थे।

इन बैठकों के दौरान मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को गलती से 5 घंटे तक रोके जाने के बारे में भी पूछताछ की गई। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नीट परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लीक होने का विरोध कर रहे छात्रों को संबोधित कर रहे थे।

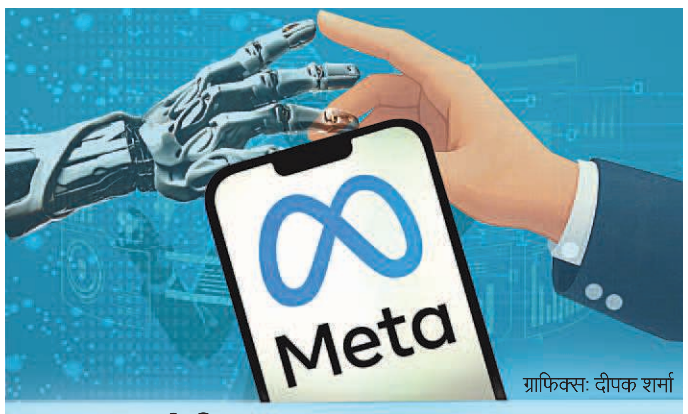

ग्राफिक्सः दीपक शर्मा

सरकार की चिंता

- संदर्भ समझे बिना सामग्री हटा रहे हैं एआई सिस्टम
- सामग्री को हटाने से रोकने के लिए मानव समीक्षक का होना है जरूरी
- मेटा को एआई निर्णय लेने की प्रक्रिया में इंसान को शामिल करने का निर्देश
- सरकार अन्य प्लेटफॉर्मों के सामग्री हटाने के मामलों का कर रही अध्ययन
- जरूरत पड़ने पर अन्य मध्यस्थों से भी संपर्क करेगी सरकार

रुपये में कारोबार के नियम हुए आसान

असित रंजन मिश्र
नई दिल्ली, 20 अगस्त

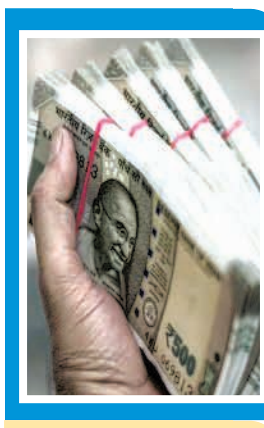

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक अहम नियामकीय बाधा दूर की है। अब निर्यातक, रुपये में भुगतान हासिल करने के बावजूद विदेशी व्यापार नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकेंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया है। इसके तहत निर्यात के बिल और भुगतान से जुड़े नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा विदेशी मुद्रा नियमन के अनुरूप कर दिया गया है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को डॉलर को चुनौती देने वाली किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने ब्रिक्स की ओर से किसी वैकल्पिक मुद्रा बनाने की कोशिश पर भी आपत्ति जताई थी और ऐसी पहल का समर्थन करने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी। भारत ने ब्रिक्स की साझा मुद्रा बनाने के विचार को साफ तौर पर खारिज किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं करता।

भारत का कहना है कि रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण किसी मौजूदा विदेशी मुद्रा व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार में रुपये के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए है। एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) की क्षेत्रीय भुगतान व्यवस्था से बाहर के देशों के साथ कारोबार करने वाले निर्यातक अब भारतीय रुपये या विदेशी मुद्रा, दोनों में अपना निर्यात अनुबंध और बिल बना सकेंगे। भुगतान भी इनमें से किसी एक मुद्रा में लिया जा सकेगा।

ईरान के मामले में रुपये में होने वाले व्यापार के लिए पहले से लागू सुरक्षा नियमों को बरकरार रखा गया है। यह बदलाव उस नियामकीय प्रक्रिया को पूरा करता है जिसकी शुरुआत जुलाई 2022 में हुई थी।

- डीजीएफटी ने अधिसूचना जारी कर विदेश व्यापार नीति, 2023 में तत्काल प्रभाव से किया बदलाव
- वैश्विक स्तर पर रुपये के इस्तेमाल की राह हुई आसान
- रुपये में भुगतान पर भी मिलेगा निर्यात का लाभ
- हालांकि ईरान के लिए पुराने नियम बरकरार

कॉपटॉल और मानसी ने कैसे की हेरफेर

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 अगस्त

सेंसेक्स पर डेरिवेटिव अनुबंध के खत्म होने की साप्ताहिक अंतिम तिथि 13 अगस्त को हाल में लागू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान कीमतों में असामान्य तौर पर अचानक उछाल दिखी। कुछ ही सेकंड में हुई इन हलचलों ने बाजार नियामक प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की निगरानी प्रणाली में गड़बड़ी का संकेत दिया। उसके बाद मामले की विस्तृत जांच की गई और सेबी ने त्वरित कार्रवाई की।

सेबी की जांच के नतीजे 46 पन्नों के अंतरिम आदेश में विस्तार से बताए गए हैं। उससे पता चलता है कि उछाल के दौरान 99 फीसदी खरीद ऑर्डर मूल्य के पीछे कॉपटॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट का हाथ था। वह जेपी मॉर्गन चेस ऐंड कंपनी का मॉरीशस का विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है। बाजार नियामक का आरोप है कि कंपनी ने सेंसेक्स में शामिल शेयरों के लिए ऐसे खरीद ऑर्डर दिए जिनकी कीमत संदर्भ मूल्य से अधिकतम 3 फीसदी से ज्यादा (तय सीमा के भीतर) थी। साथ ही कीमत में बदलाव होते ही उसने एक-तिहाई ऑर्डर अचानक रद्द कर दिए।

बाजार नियामक ने बताया कि सेंसेक्स के सभी शेयरों में एक ही समय और बेहद तालमेल के साथ ऊंची कीमतों पर दिए गए 98 करोड़ रुपये के खरीद ऑर्डर से ऐसा लगता है कि सीएएस के जरिये सेंसेक्स के सांकेतिक समान मूल्य (आईईपी) को बढ़ाकर बंद भाव में हेरफेर करने की कोशिश की गई।

बाजार नियामक ने कहा कि शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि कंपनी के एफऐंडओ पोजीशन से ऐसी हलचल पैदा करने से आर्थिक फायदा मिला।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 5.4 % बढ़ा

कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ने से देश के 9 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में बढ़कर 5.4 फीसदी हो गई। पिछले साल जुलाई में यह 3.2 फीसदी थी। पृष्ठ 4

सुधार से कारोबार दमदार पर पूंजी की दरकार

आईटी से लेकर खुदरा क्षेत्र में कोलकाता की बदली तस्वीर, मगर आर्थिक चुनौतियां बनी रहीं

35 साल उदारीकरण के

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 20 अगस्त

सितंबर 1994 की बात है जब पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर अपने कामकाज से जुड़ी छवि बदलने की दिशा में कोशिश की थी।

भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के तीन वर्ष बीतने के बाद 'लाइसेंस राज' ढह रहा था। उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने निजी निवेश के लिए द्वार खोलने पर हामी भरने के संकेत दिए। उनकी सरकार ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें अर्थव्यवस्था और 'पारस्परिक हित' के लिए 'चुनिंदा क्षेत्रों में नई तकनीक और निवेश' का स्वागत किया गया।

छह वर्ष गुजरने के बाद अप्रैल 2000 में राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की शुरुआत हुई।

निवेशकों के साथ कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए मगर उनमें से बहुत कम संयंत्रों की स्थापना या नौकरियां देने के स्रोत के रूप में तब्दील हो पाए। उस समय तक पश्चिम बंगाल की छवि उग्र मजदूर संघों और औद्योगिक अशांति वाले राज्य के रूप में बन गई थी। राज्य को लेकर बने इस नकारात्मक माहौल की वजह से कई कंपनियों ने निवेश के लिए दूसरे राज्यों की तलाश शुरू कर दी थी। इस छवि को बदलना बहुत मुश्किल साबित हुआ।

मगर नवंबर 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद संभालने के बाद राज्य की छवि सुधरने लगी। अपने खास 'अभी करो' वाले अंदाज के साथ मुख्यमंत्री ने औद्योगीकरण को अपनी कार्य योजना में प्रमुखता से शामिल कर लिया। शहर में यह बदलाव साफ दिख रहा था। साल्ट लेक और राजारहाट में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के परिसर स्थापित हुए जबकि शानदार शॉपिंग मॉल और रेस्तरांओं ने कोलकाता के व्यावसायिक स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया।

मध्य और उत्तरी कोलकाता अपनी औपनिवेशिक शिल्पकारी और पुराने व्यावसायिक इलाकों के लिए जाने जाते थे वहीं शहर के उत्तर-पूर्वी किनारों पर सॉल्ट लेक और राजारहाट नए कारोबार और सामाजिक केंद्र के तौर पर उभरे। उनके कांच और इस्पात के टावर पुराने इलाकों से बिल्कुल अलग दिखते थे।

अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिक बुनियादी ढांचे के बेजोड़ तालमेल के साथ कोलकाता शहर नए आर्थिक अवसर सृजित करते हुए लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। फोटोः विकिमीडिया कॉमन्स

उसके बाद पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में बंगाल सिलिकन वैली टेक हब जैसी परियोजनाओं से राज्य के आईटी क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला। हालांकि, इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं अब भी तैयार हो रही हैं।

भले ही नए जमाने के दफ्तरों और जगह-जगह बने फ्लाईओवर ने शहर की शक्ल-सूरत बदल दी मगर कोलकाता की छवि में बदलाव बस कुछ समय के लिए ही दिखा। हालांकि, एक समय यह उम्मीद सच लग रही थी।

तकनीक के मोर्चे पर बदलाव

वर्ष 2004 की बात है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से 'ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप' (बदलाव लाने वाले नेतृत्व) पर एक संवाद सत्र आयोजित किया गया था। विप्रो कोलकाता में एक सॉफ्टवेयर विकास केंद्र शुरू करने वाली थी और पश्चिम बंगाल में निवेश की संभावनाओं को लेकर माहौल में काफी उत्साह था। इस उत्साह का सबसे मजबूत इजहार विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी के बयान से हुआ। प्रेमजी ने कहा, 'आपके मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज वह देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं।' इस बयान में उस उम्मीद की झलक मिलती थी जो भट्टाचार्य के कार्यकाल के दौरान परवान चढ़ी थी।

भट्टाचार्य के शुरुआती कार्यकाल में सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया। हालांकि, राज्य की आईटी नीति उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जनवरी 2000 में आ गई थी मगर सरकार ने विदेश में अपनी बात रखने से पहले वर्ष 2003 और 2005 के बीच हैदराबाद, बेंगलूरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में लगभग 50 रोड शो आयोजित किए।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

लार्सन ऐंड टुब्रो

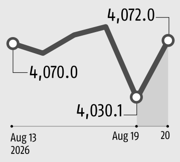

दुबई के एआई मकतूम एयरपोर्ट पर स्वचालित यात्री परिवहन प्रणाली का ऑर्डर मिला

₹ 4,030.1 पिछला बंद भाव
₹ 4,072.0 आज का बंद भाव
1.0 % ▲

आदित्य बिड़ला कैपिटल

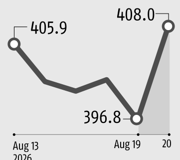

स्वर्ण ऋण कारोबार में कदम रखा, 3 साल में 1,000 शाखाएं खोलने की योजना

₹ 396.8 पिछला बंद भाव
₹ 408.0 आज का बंद भाव
2.8 % ▲

ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स

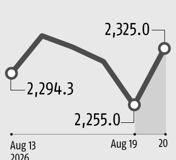

फ्लुटिकासोन प्रोपियोनेट नेजल स्प्रे के लिए मिली यूएसएफडीए से मंजूरी

₹ 2,255.0 पिछला बंद भाव
₹ 2,325.0 आज का बंद भाव
3.1 % ▲

मैनकाइंड फार्मा

देश में 2 इंसुलिन एनालॉग्स के विपणन के लिए चेनान बायोफार्मा संग खास समझौता

₹ 2,391.0 पिछला बंद भाव
₹ 2,385.0 आज का बंद भाव
-0.3 % ▼

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज

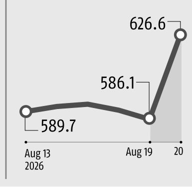

तिरुवनंतपुरम में ब्रिगेड स्क्वायर पर अमेरिका की हेल्थएज संग पट्टे का करार

₹ 586.1 पिछला बंद भाव
₹ 626.6 आज का बंद भाव
6.9 % ▲

संक्षेप में

आदित्य बिड़ला कैपिटल स्वर्ण ऋण कारोबार में

आदित्य बिड़ला कैपिटल का गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार अब गोल्ड लोन के क्षेत्र में भी उतर गया है। कंपनी इसके लिए अगले तीन साल के दौरान 1,000 शाखाएं खोलने की योजना बन रही है। इससे पहले एक अन्य बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) टाटा कैपिटल ने पिछले महीने केरलम की योगक्षेमम लोन्स में लगभग 89 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर स्वर्ण ऋण कारोबार में प्रवेश किया था। पिछले कुछ सालों के दौरान स्वर्ण ऋण कारोबार में जबरदस्त तेजी देखी गई है। इसलिए, अलग-अलग तरह के कारोबार करने वाली एनबीएफसी इस श्रेणी में मौजूदगी बढ़ा रही हैं। श्रीराम फाइनैंस, एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनैंस और पीरामल फाइनैंस जैसी कंपनियां भी अपना गोल्ड लोन बिजनेस बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। *बीएस*

सीगल इंडिया को मिले 2,423 करोड़ रु के ठेके

बुनियादी ढांचा विकास कंपनी सीगल इंडिया को उसके संयुक्त उद्यमों के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अरुणाचल प्रदेश में एनएच-913 पर सड़क निर्माण के लिए 2,423.70 करोड़ रुपये के पांच ठेके मिले हैं। कंपनी के गुरुवार को जारी बयान के अनुसार सीगल इंडिया लिमिटेड और राजिंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम को एनएच-913 के 'बाइले-मिगिंग' खंड में 17.812 किलोमीटर से 55.377 किलोमीटर तक के हिस्से में सड़क निर्माण के लिए 274.08 करोड़ रुपये का इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) ठेका मिला है। इस संयुक्त उद्यम में सीगल इंडिया की 70 प्रतिशत और राजिंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। परियोजना में 48 महीने की निर्माण अवधि और उसके बाद पांच साल की रखरखाव अवधि शामिल है। इसके अलावा, सीगल इंडिया को सुशी इन्फ्रा ऐंड माइनिंग लिमिटेड के साथ अपने संयुक्त उद्यम के माध्यम से चार ठेके मिले हैं। इनकी कुल राशि 2,149.62 करोड़ रुपये है। *भाषा*

इंडियन होटल्स ने खोला लखनऊ में ताज पैलेस

टाटा समूह के स्वामित्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने लखनऊ में 181 कमरों वाला ताज पैलेस होटल खोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को होटल का उद्घाटन किया। आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी पुनीत चटवाल ने कहा, 'जैसे-जैसे भारत का आर्थिक और पर्यटन परिदृश्य लगातार विस्तृत हो रहा है, बुनियादी ढांचे के विकास, बढ़ते निवेश और पर्यटकों की बढ़ती संख्या से प्रेरित होकर लखनऊ जैसे शहर विकास के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।' चटवाल ने कहा कि शहर में दूसरे ताज होटल की शुरुआत क्षेत्र की प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। *भाषा*

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following:

Sr. No.	Title and Tender ID No	Bid Due Date	Bid Opening Date
1	hvac Works for Sant Tukaram Maharaj Natyagruh Tender ID - **2026_ASCDC_1329674_1**	26/08/2026 17:00:00	27/08/2026 17:00:00

The tender documents can be downloaded from **https://www.mahatenders.gov.in**

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

SBI

स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप, कॉरपोरेट सेंटर,
द आर्केड, दूसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड केंद्र, कफ परेड, मुंबई – 400005

ई–नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों (अनुमत स्थानान्तरणकर्ता एनबीएफसी/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/एआरसी) को स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण

भारतीय स्टेट बैंक पात्र प्रतिभागियों से, भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य नियामकों द्वारा जारी लागू विनियमों के अधीन, 1 (एक) खाते के ₹27.27 करोड़ (मात्र सत्ताईस करोड़ सत्ताईस लाख रुपये) के मूल निधि आधारित बकाया के स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोज़र के हस्तांतरण हेतु 'जैसा है जहाँ है'; 'जैसा है वैसा है'; 'जो कुछ है वही'; और 'बिना किसी उत्तरदायित्व के आधार पर' ई–नीलामी के माध्यम से, रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें. पात्र प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे गैर–प्रकटीकरण समझौता (वेब नोटिस में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार) निष्पादित करें। यदि गैर–प्रकटीकरण समझौता निष्पादित नहीं होता है, तो कृपया ई–मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क करें। कृपया बैंक की वेब साइट https://sbi.bank.in पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें (वेब नोटिस).

कृपया ध्यान दें कि बैंक किसी भी चरण पर प्रस्तावित ई–नीलामी को आगे न बढ़ाने या ई–नीलामी की तिथि अथवा किसी भी नियम व शर्तों में बिना कोई कारण बताए बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना https://sbi.bank.in वेबसाइट पर "SBI in the news > Auction Notices > ARC & DRT" लिंक के तहत संशोधन सूचना (Corrigendum) के रूप में दी जाएगी. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

स्थान: मुंबई **द्वारा जारी**
तिथि: 21.08.2026 **उप– महाप्रबंधक (क्रेडिट और एआरसी)**

भारत में पहला ब्रांडेड आवास पेश करेगी विनडम होटल्स

गुलवीन औलख
नई दिल्ली, 20 अगस्त

"हम पहले से ही लोकेशन की तलाश में लग गए हैं। हम साझेदारों पर भी नजर बनाए हुए हैं। हमारा पहला साझेदार साल के आखिर तक बन जाएगा।"

दिमित्रिस मानिकिस,
यूरोप, पश्चिम एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका (ईएमईए) मामलों के अध्यक्ष, विनडम होटल्स ऐंड रिसॉर्ट्स

अमेरिका स्थित विनडम होटल्स ऐंड रिसॉर्ट्स इस साल के अंत तक भारत में अपना पहला ब्रांडेड रेजिडेंस पेश करने की तैयारी में है। कंपनी के यूरोप, पश्चिम एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका (ईएमईए) मामलों के अध्यक्ष दिमित्रिस मानिकिस ने बिजनेस स्टैंडर्ड को इसकी जानकारी दी।

गुरुवार को, विनडम ने भारत में अपना 'विएना हाउस' ब्रांड पेश किया।

नैस्डैक में सूचीबद्ध यह होटल फर्म 'रमाडा' और 'डेज इन' जैसे ब्रांडों का संचालन करती है और उसने वर्ष 2028 तक होटलों और कमरों की संख्या के हिसाब से अपनी उपस्थिति को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा, 'हम पहले से ही लोकेशन की तलाश में लग गए हैं। हम साझेदारों पर भी नजर बनाए हुए हैं। हमारा पहला साझेदार साल के आखिर तक बन जाएगा।' गुरुवार को एक बातचीत में मानिकिस ने कहा, 'मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने इलाके के दूसरे हिस्सों में ब्रांडेड घरों में जो वृद्धि देखी है, उसका फायदा उठाना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भारत पीछे न रहे।'

विनडम भारतीय ब्रांडेड घरों के बाजार में सबसे नई प्रवेश करने वाली कंपनियों में से एक होगी। इस बाजार में पिछले साल जैकब्स एंड कंपनी, लैम्बोर्गिनी टोरिनो और एली साब जैसे ब्रांडों के साथ समझौतों में तेजी देखी गई है, हालांकि ये लग्जरी ब्रांड हैं।

विनडम ब्रांडेड घरों को मिड-स्केल सेगमेंट में चलाएगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वह वैश्विक बाजार में अपने सभी 25 होटल ब्रांड भी चलाती है और अभी संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये, थाईलैंड, पुर्तगाल, मिस्र और हाल में सऊदी अरब के बाजार में विनडम रेजिडेंस, विनडम ग्रैंड रेजिडेंस और रमाडा रेजिडेंस चला रही है।

नोएसिस होटल एडवाइजर्स के अनुसार, भारत में ब्रांडेड रेजिडेंस परियोजनाओं का कुल विकास मूल्य लगभग 10.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 19 निर्माण के अधीन हैं और 17 की घोषणा की जा चुकी है। नोएसिस होटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ नंदीवर्धन जैन ने कहा, '2026 के दौरान और अधिक घोषणाएं अपेक्षित हैं तथा शुरुआती व्यवहार्यता, उत्पाद योजना या ब्रांड चयन में 20 से अधिक अतिरिक्त परियोजनाएं हैं। यह श्रेणी मुंबई और एनसीआर से आगे बढ़कर टियर-1 और टियर-2 शहरों और गोवा, अलीबाग, कर्जत, इगतपुरी, कसौली, कूर्ग और ऋषिकेश जैसे लीजर बाजारों में भी फैल गई है।'

मानिकिस ने यह भी बताया कि मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट बढ़ने से भारतीय बाजार विकसित हो रहा है, जिसमें होटल या रिटेल कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ होटल या हॉस्पिटैलिटी कंपनी द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले आवासीय खंड शामिल हैं।

होटल परिचालन के संदर्भ में मानिकिस ने बताया कि विनडम के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लिए भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है, जो वैश्विक पोर्टफोलियो प्रवाह का 58 प्रतिशत है। इससे यह दक्षिण एशियाई देश वैश्विक वृद्धि के लिए, उसके सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक बन गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम से हाई कोर्ट जाने को कहा

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 20 अगस्त

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के उस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें कंपनी के स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाया के लिए लगभग 801.91 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को कैश कराने के दूरसंचार विभाग के फैसले को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के पीठ ने आरकॉम को उच्च न्यायालय से राहत मांगने की अनुमति दी, लेकिन ऐसा करने के लिए एक सप्ताह तक मौजूदा स्थिति बनाए रखने की कंपनी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि आरकॉम उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दे सकती है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीएस) के तहत स्पेक्ट्रम पर फरवरी 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने, अपने आप में, गारंटी के आह्वान को उचित नहीं ठहराया।

न्यायालय ने यह भी साफ किया कि उसने आरकॉम की चुनौती के गुण-दोष की जांच नहीं की है।

यह याचिका आरकॉम के समाधान पेशेवर द्वारा येस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नैशनल बैंक की याचिकाओं के साथ दायर की गई थी, जिन्होंने दूरसंचार कंपनी के स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए गारंटी दी थी।

ललित मोदी : संपत्ति हस्तांतरित करने का फैसला बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता का वह फैसला बरकरार रखा है, जिसमें कारोबारी ललित मोदी को वसंत विहार स्थित अपनी प्रॉपर्टी बीडीआर बिल्डर्स ऐंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की प्रक्रिया पूरी करना का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने साल 2016 के उस फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने पाया कि मोदी यह साबित नहीं कर पाए कि मध्यस्थ इस मामले में काम करने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य था या फिर उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर संदेह करने के पर्याप्त आधार थे। यह विवाद वसंत विहार के 32, पश्चिमी मार्ग स्थित 858 वर्ग गज की प्रॉपर्टी से जुड़ा है।

भारत में इंसुलिन एनालॉग का विपणन करेगी मैनकाइंड फार्मा

संकेत कौल
नई दिल्ली, 20 अगस्त

भारत की दवा विनिर्माता मैनकाइंड फार्मा ने चीन की चोंगकिंग चेनआन बायो फार्मास्युटिकल्स के साथ खास लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसके तहत वह भारतीय बाजार में उसके दो बेसल इंसुलिन एनालॉग्स की बिक्री करेगी। इस साझेदारी में इंजेक्शन से दी जाने वाली दो दवाओं - इंसुलिन डेग्लुडेक तथा इंसुलिन डेग्लुडेक व एस्पार्ट के संयोजन की बिक्री शामिल है। इन दवाओं का इस्तेमाल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज बीमारी के इलाज में किया जाता है।

इस समझौते का मकसद मधुमेह श्रेणी में मैनकाइंड की मौजदगी मजबूत करना और इंजेक्शन वाले आधुनिक उपचारों के पोर्टफोलियो का विस्तार करना है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि मैनकाइंड इन इंसुलिन एनालॉग की कीमत प्रतिस्पर्धी रख सकती है। इंसुलिन डेग्लुडेक और इंसुलिन एस्पार्ट के संयोजन को भारत में आम तौर पर नोवो नॉर्डिस्क राइजोडेग के नाम से बेचती है। 3 मिलीलीटर पेनफिल या कार्ट्रिज वाले इस संयोजन के दाम अमूमन 1,200 रुपये से 1,600 रुपये के बीच होते हैं।

चीन की चोंगकिंग चेनआन बायो फार्मा के साथ मैनकाइंड फार्मा ने विशेष लाइसेंसिंग समझौता किया है

मैनकाइंड फार्मा के वरिष्ठ अध्यक्ष (बिक्री और विपणन) आतिश मजूमदार ने कहा, 'यह साझेदारी भारत में मरीजों की आधुनिक उपचार तक पहुंच बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता मजबूत करती है और साथ ही इंजेक्टेबल डायबिटीज श्रेणी में मौजूदगी का विस्तार करती है।'

जुलाई 2026 में मूविंग एनुअल टर्नओवर (एमएटी यानी पिछले 12 महीनों का राजस्व) के आधार पर डायबिटीज के इलाज से मैनकाइंड की बिक्री से होने वाली कमाई 1,073 करोड़ रुपये दर्ज की गई। फिलहाल डायबिटीज श्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत है।

कंपनी के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हालांकि वर्तमान बिक्री का अधिकांश हिस्सा ओरल एंटी-डायबिटिक दवाओं से है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इंसुलिन जैसी इंजेक्टेबल दवाएं भी इस उपचार क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा बनेंगी।'

स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों से सस्ता पड़ेगा गाड़ी रखना

सोहिनी दास और शाइन जेकब
मुंबई/चेन्नई, 20 अगस्त

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमिट के तहत संचालित चुनिंदा बैटरी-इलेक्ट्रिक, कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) और हाइड्रोजन चालित वाहनों को पांच वर्ष ज्यादा चलाने का प्रस्ताव दिया है। उद्योग के जानकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र के इस कदम से इन वाहनों के स्वामित्व की कुल लागत और कबाड़ राशि में सुधार हो सकता है।

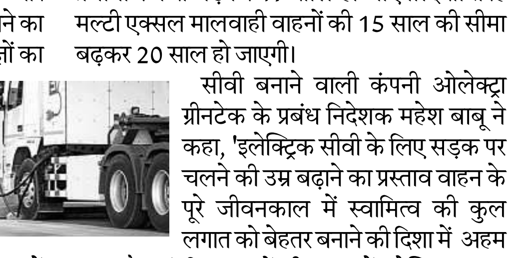

अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि ज्यादा दूरी तय करने वाले ट्रकों के लिए, बढ़ाई गई नियमन अवधि का कितना हिस्सा असल में आर्थिक रूप से उपयोगी जीवनकाल में बदलेगा। प्रस्तावित बदलाव खास तौर पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 88 के तहत आने वाले वाहनों के लिए है। यह सभी वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) के लिए सामान्य विस्तार नहीं है।

अगर इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो मल्टी एक्सल वाहनों के अलावा माल ढोने वाले वाहनों के लिए मौजूदा 12 साल की उम्र सीमा पात्र क्लीन फ्यूल वाहनों के लिए प्रभावी रूप से बढ़कर 17 साल हो जाएगी। इसी तरह मल्टी एक्सल मालवाही वाहनों की 15 साल की सीमा बढ़कर 20 साल हो जाएगी।

सीवी बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के प्रबंध निदेशक महेश बाबू ने कहा, 'इलेक्ट्रिक सीवी के लिए सड़क पर चलने की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव वाहन के पूरे जीवनकाल में स्वामित्व की कुल लागत को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मूल रूप से ज्यादा कुशल होते हैं और उनमें यांत्रिक पुर्जे कम होते हैं। इससे वाहन का लंबे समय तक और ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल किया जा सकता है।'

ऐडफैक्टर्स ने सीनेट-एसएचजे में लिया बहुलांश हिस्सा

देश की सबसे बड़ी जनसंपर्क कंपनी ऐडफैक्टर्स पीआर ने ऑस्ट्रेलिया की संचार सलाहकार कंपनी सीनेट-एसएचजे में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के साथ कंपनी ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया है।

दोनों कंपनियों ने गुरुवार को संयुक्त बयान में कहा, 'यह सौदा दो स्वतंत्र कंपनियों को एक साथ लेकर आया है, जिनकी क्षमताएं और विचार एक-दूसरे के पूरक हैं।' हालांकि सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। सीनेट-एसएचजे अपने ब्रांड, नेतृत्व और ग्राहक टीमों को बरकरार रखेगी तथा सिडनी और मेलबर्न स्थित अपने कार्यालयों से काम जारी रखेगी। *भाषा*

सवाल जवाब

जीएसके इंडिया का लक्ष्य 2030 तक दोगुना राजस्व

जीएसके इंडिया जनरल-मेडिसिन बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए ऑन्कोलॉजी और एडल्ट वैक्सीन को अपने अगले ग्रोथ इंजन के तौर पर देख रही है। जीएसके इंडिया के प्रबंध निदेशक भूषण अक्षिकर ने सोहिनी दास को दिए वीडियो इंटरव्यू में बताया कि कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक अपना राजस्व बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपये करना है। इसमें ऑन्कोलॉजी बिजनेस के अगले पांच साल में 750–1,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। बातचीत के अंश ...

अभी जीएसके इंडिया के राजस्व में ऑन्कोलॉजी का योगदान बहुत कम है। अगले पांच साल में यह कितना योगदान दे सकता है?

एक दशक से भी ज्यादा समय पहले, हमारा एक ऑन्कोलॉजी बिजनेस था जिसे नोवार्टिस के साथ एक वैश्विक एसेट-स्वैप डील में बेच दिया गया था। हम उन क्षमताओं को फिर से बना रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे ऑर्डर मजबूत हैं। हमने स्त्री रोग संबंधित समस्याओं के क्षेत्र में अपना ऑन्कोलॉजी व्यवसाय शुरू किया, जिसमें प्रमुख एडवांस्ड और रीकरेंट एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए जेम्परली और रीकरेंट डिम्बग्रंथि कैंसर के लिए जेजुला शामिल हैं। हमें रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी मल्टीपल मायलोमा के उपचार के लिए ब्लैरेप की मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही पेश किया जाएगा। हम अगले 12 महीनों के भीतर मायलो-फाइब्रोसिस के लिए ओम्जारा को भी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं।

मुझे लगता है कि अगले पांच साल में ऑन्कोलॉजी हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा होगा। मैं कोई पक्का आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि पांच साल में ऑन्कोलॉजी का बिजनेस लगभग 750 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। ये अनुमानित आंकड़े हैं।

जीएसके के क्लीनिकल ट्रायल में भारत की बढ़ती भागीदारी उत्पाद पेशकशों की रफ्तार बढ़ाने में किस तरह मदद कर रही है?

जब चार साल पहले मुझे यह जिम्मेदारी मिली थी, तब लगभग 12 या 13 ट्रायल चल रहे थे। अभी 33 वैश्विक और स्थानीय चिकित्सकीय ट्रायल चल रहे हैं या उनकी योजना है। इनमें से 27 प्रमुख अध्ययन हैं जो वैश्विक क्लिनिकल-ट्रायल रोडमैप का हिस्सा हैं। पिछले 24 महीनों में, हमने यह पक्का किया है कि हर वैश्विक परिसंपत्ति के क्लिनिकल-डेवलपमेंट प्लान में भारत भी शामिल हो।

आप जीएसके के पीडियाट्रिक और एडल्ट वैक्सीन व्यवसाय के बीच संतुलन में किस तरह का बदलाव देखते हैं?

बच्चों के टीके महत्त्वपूर्ण बने रहेंगे क्योंकि भारत में हर साल 2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। भारत में हर सात सेकंड में एक बच्चे को जीएसके का टीका लगाया जाता है। हमारे लगभग 4,000 करोड़ रुपये के कारोबार में टीका व्यवसाय का योगदान 750 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

कोविड-19 से पहले, वयस्कों के टीकाकरण का सिस्टम लगभग न के बराबर था। उस स्थिति से आगे बढ़ते हुए शिंगल्स से बचाव वाली वैक्सीन 'शिंग्रिक्स' अब सालाना कुल बिक्री के आधार पर 100 करोड़ रुपये का ब्रांड बन गई है। हर महीने लगभग 20,000 मरीज यह वैक्सीन लगवाते हैं और शिंग्रिक्स तेजी से बढ़ रही है। हमें अरेक्सवी के लिए डीसीजीआई से मार्केटिंग ऑथराइजेशन भी मिल गया है। हमने इसे अगले 12 महीने में पेश करने की योजना बनाई है।

पोर्टफोलियो में बदलाव के साथ राजस्व और मार्जिन से आपकी क्या उम्मीदें हैं?

हमारा लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक कारोबार को बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपये तक ले जाना है। यह लक्ष्य अभी भी कायम है। हमारा पूरा ध्यान फिलहाल परिचालन क्षमता बढ़ाने, सकल मार्जिन बेहतर करने और फैक्टरी व आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कमियों और फालतू खर्चों को हटाने पर है। हमारा मकसद कुल बिक्री को बढ़ाते हुए मार्जिन को मौजूदा स्तर पर बनाए रखना है।

एक फायदा यह है कि वैश्विक संगठन आरऐंडडी के काम, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल भी शामिल हैं, के लिए फंडिंग करता है। ऑन्कोलॉजी और हीमेटोलॉजी से जुड़े परिसंपत्तियों के लिए 2,000 या 3,000 लोगों की टीम जरूरत नहीं होती। इनके लिए सिर्फ 20 या 30 बहुत काबिल, साइंस की समझ रखने वाले टीम सदस्यों की जरूरत हो सकती है। इनमें से हर एसेट की कीमत अलग-अलग 300 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

मुंबई संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता अश्विन ठाकुर खेओरा द्वारा मै. दांगट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीघा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीघा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 022-40275300/40275400
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

एमपीसी के सख्त रुख वाले मिनट्स से बॉन्ड यील्ड बढ़ी

अंजलि कुमारी
मुंबई, 20 अगस्त

सरकारी बॉन्ड यील्ड में गुरुवार को तेजी आई। इसकी वजह बुधवार शाम जारी हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के मिनट्स (ब्योरे) से मिले सख्त रुख के संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में दिन में हुई तेज बढ़ोतरी थी। इस कारण बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई। डीलरों ने यह जानकारी दी।

बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 6.87 फीसदी पर बंद हुई। एक दिन पहले यह 6.82 फीसदी पर बंद हुई थी। 5 साल के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 7 आधार अंक बढ़कर 6.52 फीसदी पर पहुंच गई।

बाजार के प्रतिभागियों का कहना है कि बाजार अब अक्टूबर की शुरुआत में होने वाली अगली नीतिगत समीक्षा में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना को ध्यान में रख रहा है। उन्होंने बताया कि एमपीसी की चर्चा तब हुई थी, जब कच्चा तेल 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहा था और उस स्तर पर कमेटी का रुख नरम था। अब कच्चे तेल की कीमत 94 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। इसलिए बाजार के प्रतिभागियों का मानना है कि नीति को सख्त करने की बात और मजबूत हुई है।

आईसीआईसीआई बैंक के अर्थशास्त्रियों ने एक नोट में कहा, एमपीसी की बैठक के मिनट्स को सख्त रुख वाला माना जाना चाहिए जबकि नीतिगत बयान को नरम रुख वाला माना गया था। इन दोनों में बड़ा अंतर यह है कि आने वाले महीनों में मजबूत मांग के कारण महंगाई के जोखिमों के व्यापक होने पर जोर दिया गया है।

अब बाज़ार का ध्यान अगस्त और सितंबर के सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर होगा, जिनसे आने वाले समय में ब्याज दरों की संभावनाएं तय हो सकती हैं। डीलरों का कहना है कि अगर महंगाई और बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना और मजबूत हो जाएगी।

एक प्राइमरी डीलरशिप के डीलर ने कहा, बैठक के मिनट्स के लहजे ने चौंका दिया। नीतिगत बैठक के बाद हुई बातचीत में एमपीसी की टिप्पणी का लहजा काफी नरम लग रहा था जबकि बाजार ज्यादा सख्त रुख की उम्मीद कर रहा था। मिनट्स से पता चला कि लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी बातों की तुलना में काफी ज्यादा सख्त था। इस वजह से लोगों ने अपनी पोजीशन बदलीं और सौदे काटे।

बाजार के प्रतिभागियों का कहना है कि ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) कर्व के हिसाब से अगली नीतिगत बैठक में कम से कम 20 आधार अंकों की दर बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही, यह कर्व अगले तीन महीनों में कुल मिलाकर 25 आधार अंकों की सख्ती का संकेत दे रहा है। यह स्थिति एमपीसी की मिनट्स के बाद बॉन्ड बाजार में दिखे सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीद के अनुरूप है और इसके साथ ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक यील्ड में मजबूती का दबाव भी बना हुआ है।

गुरुवार को एक साल की ओआईएस दर, जो निकट भविष्य में ब्याज दरों के अनुमान का सबसे अहम पैमाना है, 13 आधार अंक बढ़कर 5.94 फीसदी पर बंद हुई। इसके अलावा, फेडरल रिजर्व के बॉन्ड खरीदने के ऐलान के बाद भी अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इससे मिली राहत कुछ ही समय के लिए रही।

एक प्राइवेट बैंक के ट्रेजरी प्रमुख ने कहा, फेड की ओर से बॉन्ड खरीदने के ऐलान के बावजूद अमेरिकी यील्ड धीरे-धीरे बढ़ रही है। बुधवार को इसमें 5 आधार अंक की राहत मिली थी, लेकिन आज दिन के दौरान यह फिर से बढ़ गई।

हाल ही में पूंजी आने के बावजूद रुपये को बहुत कम राहत मिली है और वैश्विक संकेतों की वजह से यह दबाव में बना हुआ है। हालांकि एफसीएनआर (बी) योजना के जरिये आई रकम ने कुछ सहारा दिया है, लेकिन रुपये की वैल्यू में कोई खास बढ़ोतरी लाने के लिए यह काफी नहीं रहा है। स्थानीय मुद्रा 95.71 प्रति डॉलर पर बंद हुई जबकि एकत दिन पहले यह 95.76 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी।

रुख में बदलाव

- नीतिगत बैठक के बाद हुई बातचीत में एमपीसी की टिप्पणी का लहजा काफी नरम लग रहा था जबकि बाजार ज्यादा सख्त रुख की उम्मीद कर रहा था
- मिनट्स से पता चला कि लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी बातों की तुलना में काफी ज्यादा सख्त था

निफ्टी में गिरावट का सिलसिला थमा

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 20 अगस्त

गुरुवार को वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से लंबी अवधि वाले बॉन्डों की यील्ड में हो रही बढ़ोतरी को रोकने की योजना की घोषणा के बाद बेंचमार्क निफ्टी में लगातार सात दिनों से हो रही गिरावट का सिलसिला थम गया।

निफ्टी 50 इंडेक्स 154 अंक यानी 0.64 फीसदी की बढ़त के साथ 24,232 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 628 अंक यानी 0.82 फीसदी चढ़कर 77,538 पर बंद हुआ। सेंसेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों की साप्ताहिक एक्सपायरी के दिन दोनों बेंचमार्क के बीच 0.18 फीसदी अंक का अंतर रहा। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 2.7 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 491 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

17 अगस्त को 30 साल वाली अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 5.31 फीसदी पर पहुंच गई। यह उसका कई दशकों का उच्चतम स्तर था, लेकिन बुधवार को अमेरिकी ट्रेजरी के यह कहने के बाद कि वह अपने लिक्विडिटी सपोर्ट बायबैक ऑपरेशन का आकार कम से कम दोगुना कर देगा, यह यील्ड घटकर 5.23 फीसदी के आसपास आ गई। हालांकि, गुरुवार को यील्ड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह चार आधार अंक ऊपर चढ़ गई।

इस बीच, ब्रेंट क्रूड 2.51 फीसदी बढ़कर 92.29 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द शांति समझौते की उम्मीदें कम हैं। क्रूड की ऊंची कीमतें भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, जो अपनी तेल की जरूरतों का 80 फीसदी से ज्यादा आयात करता है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी की घोषणा के बाद मनोबल बेहतर हुआ है। लेकिन ऊर्जा की ऊंची लागत के कारण घरेलू शेयरों के लिए जोखिम अभी भी ज्यादा बना हुआ है।

आगे चलकर पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक घटनाक्रम और अगले हफ्ते जैक्सन हॉल इकनॉमिक सिम्पोजियम में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श का भाषण बाजार की दिशा तय करेंगे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, वैश्विक बॉन्ड यील्ड में तेजी रोकने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी के दखल से बाजार को बहुत जरूरी राहत मिली। इससे बाजार में जबरदस्त और व्यापक रिकवरी हुई। घरेलू बाजार में हफ्ते भर से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। इस दखल का असर डॉलर पर पड़ा है। डॉलर कमजोर होने, रुपया मजबूत होने और यील्ड का दबाव घटने से उभरते बाजारों का आकर्षण बढ़ा है। रिकवरी सभी सेक्टर में देखी गई, जिसमें मुख्य रूप से आईटी और वित्तीय शेयरों में तेजी का योगदान रहा क्योंकि यील्ड में नरमी से खर्च को बढ़ावा मिलता है।

नायर ने आगे कहा, निकट भविष्य का आउटलुक वैश्विक यील्ड, ऊर्जा की कीमतों और भूराजनीतिक घटनाक्रम की दिशा पर निर्भर करेगा। साथ ही, आय की रफ्तार और विदेशी निवेश को बनाए रखने के लिए लगातार स्थिरता की जरूरत होगी।

बाजार में चढ़ने व गिरने वाले शेयरों का अनुपात सकारात्मक रहा और बीएसई पर 2,373 शेयरों में तेजी आई जबकि 1,951 गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 583 करोड़ रुपये के शुद्ध बिकवाल रहे जबकि देसी संस्थागत निवेशकों ने 3,538 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद से बाजार को सहारा दिया।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज में शोध प्रमुख (वेल्थ मैनेजमेंट) सिद्धार्थ खेमका ने कहा, लगातार सात कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग और वैश्विक बाजार से मिले मजबूत संकेतों के कारण भारतीय इक्विटी बाजार में मामूली रिकवरी के साथ उतार-चढ़ाव सीमित रहने की उम्मीद है।

बॉन्ड टोकनाइजेशन का परीक्षण शुरू करेगा सेबी

इस परीक्षण योजना में आरबीआई भी भागीदार

खुशबू तिवारी
मुंबई, 20 अगस्त

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) बॉन्ड के टोकनाइजेशन के लिए एक पायलट योजना बना रहा है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि क्या शेयर्ड-लेजर टेक्नॉलजी से निपटान प्रक्रिया को तेज और ज्यादा कुशल बनाया जा सकता है।

इस पायलट परियोजना को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि क्या शेयर्ड लेजर से प्रतिभूतियों और पैसे को एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे मिलान की लागत कम हो। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह स्मार्ट अनुबंधों के जरिये ऑटोमेटेड कूपन पेमेंट और ब्याज जैसी अन्य चीजों की व्यवहार्यता पर भी गौर करेगा।

यह पहल कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए सेबी के प्रयासों का हिस्सा है। सिंह ने स्पष्ट किया कि टोकनाइजेशन का उद्देश्य एक अलग ट्रेडिंग बाजार बनाना नहीं है, बल्कि यह आकलन करना है कि क्या टेक्नॉलजी मौजूदा बाजार को सरल, तेज और अधिक कुशल बना सकती है।

साथ ही सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड रीपो बाजार का दायरा बढ़ाने के उपायों की संभावना भी खंगाल रहा है, जो वर्तमान में समग्र रीपो बाजार का 1 प्रतिशत से भी कम है। सिंह ने कहा कि आमतौर पर एक दिन में कॉरपोरेट बॉन्ड रीपो का कारोबार लगभग 6,000 करोड़ रुपये होता है।

नियामक प्रतिभूति उधार लेने-देने के साथ-साथ शॉर्ट सेलिंग के लिए सक्षम ढांचे के उपायों पर भी विचार कर रहा है ताकि इस सेगमेंट को व्यापक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ मुद्दे सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और इसके लिए नियामक संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है।

ये उपाय ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब सेबी कॉरपोरेट बॉन्डों के सेकंडरी बाजार में तरलता सुधारना चाहता है।

वित्तीय शेयरों में बढ़ा एफपीआई का निवेश, आईटी में भी खरीद

अभिषेक कुमार
मुंबई, 20 अगस्त

अगस्त के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयरों में अपनी खरीदारी बढ़ाई। इसमें वित्तीय सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इस क्षेत्र में 1 से 15 अगस्त के बीच कुल 6,535 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में 2,669 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी।

इसके बाद ऑटोमोबाइल और वाहन कलपुर्जा का स्थान रहा, जिनमें 4,405 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। उपभोक्ता सेवा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी जबरदस्त खरीदारी देखी गई। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में 3,298 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पसंदीदा बने आईटी शेयरों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखा और अगस्त के पहले पखवाड़े में इनमें 2,530 करोड़ रुपये का और निवेश आया।

2026 की पहली छमाही में एफपीआई मुख्य रूप से भारतीय आईटी शेयरों के शुद्ध बिकवाल बने रहे। इसकी वजह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से होने वाले बदलाव, टेक्नॉलजी पर खर्च में कमी और राजस्व को लेकर अनिश्चितता जैसी चिंताएं थीं, जिनका असर इस क्षेत्र पर पड़ा। इस बिकवाली के कारण आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई और 2026 की पहली छमाही में निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 30 फीसदी गिर गया।

हालांकि, जुलाई में वैश्विक एआई ट्रेड पलटने के साथ ही यह रुझान तेजी से बदल गया। एआई और सेमीकंडक्टर शेयरों के बहुत ज्यादा मूल्यांकन की बढ़ती चिंताओं के कारण निवेशकों ने भारतीय आईटी सेवा कंपनियों की तुलनात्मक अपील पर फिर से विचार किया। आईटी का प्रदर्शन पहले काफी खराब रहा था। एफपीआई की खरीदारी के दम पर जुलाई में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 16.7 फीसदी की बढ़त हुई।

एफपीआई के डिजिटल हस्ताक्षर वाले पावर ऑफ अटॉर्नी को मंजूरी

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को जोड़ने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के मकसद से बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को एफरीआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी को स्वीकार करने की अनुमति दे दी। यह अनुमति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नियमों के मुताबिक दी गई है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा, इससे पावर ऑफ अटॉर्नी के नोटराइजेशन, एपोस्टिलाइजेशन या कांसुलरइजेशन की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे एफपीआई को जोड़ने में लगने वाला कुल समय कम होता है और एफपीआई आवेदकों के लिए कारोबारी सुगमता बेहतर होती है। ये बदलाव गुरुवार से लागू हो गए हैं। बाजार नियामक ने पिछले कुछ सालों में पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिसमें कॉमन ऐप्लिकेशन फॉर्म और पंजीकरण दस्तावेज के लिए भारतीय डिजिटल सिग्नेचर के इस्तेमाल की अनुमति शामिल है। *बीएस*

सोने में बढ़त, चांदी भी उछली

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। कमजोर अमेरिकी डॉलर के बीच निवेशकों के बहुमूल्य धातुओं की ओर रुख करने से सोना 4,300 रुपये बढ़कर तीन महीने के उच्चतम स्तर 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी में 10,000 रुपये की उछाल आई। *भाषा*

RUSHIL DECOR LIMITED

RUSHIL DECOR LIMITED WE'LL MAKE IT

Regd. Office: S. No. 149, Near Kalyanpura Patia, Village Itla, Gandhinagar mansa Road, Ta. Mansa, Dist. Gandhinagar-382845, Gujarat, India.
Corporate Office: Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off Sindhu Bhavan Road, Shilaj, Ahmedabad-380059, Gujarat, India.
Ph: +91-79-61400400 | **Fax:** +91-79-61400401
Email: ipo@rushil.com | **Website:** www.rushil.com
CIN: L25209GJ1993PLC019532

NOTICE OF 32ND (THIRTY SECOND) ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that in compliance with General Circular No.20/2020, 02/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read together with other relevant circulars issued by MCA in this regard and Circular No.SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and SEBI/HO/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as "Circulars") and in compliance with all other applicable laws, the **32nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of RUSHIL DECOR LIMITED** will be held at **10.30 AM** on **Monday, 28th day of September, 2026 through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (RTA)/Depository Participants. Members holding shares in dematerialized mode and whose e-mail address are not registered, are requested to register their e-mail addresses with their relevant Depository Participants. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 will also be available on the Company's website at www.rushil.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and at National Stock Exchanges of India limited at www.nseindia.com and the AGM Notice will also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting facility) at https://www.evoting.nsdl.com/ in due course. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM is provided in the Notice of AGM.

Further, In accordance with Regulation 36(1)(b) of Listing Regulations, a communication/letter shall be sent to shareholders whose Email IDs are not registered with DP, providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for FY 2025-26 can be accessed.

The company has fixed **Tuesday, 8th September, 2026** as the Record date for the purpose of determining the entitlement of final dividend of ₹ 0.05 (Five paisa) per equity share of ₹ 1/- each (@5%) as recommended by the Board, for the financial year 2025-26 on the paid up equity share capital of the Company, if declared at the ensuing Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date **Monday, 21st day of September, 2026** may cast their vote electronically on the business as set in the notice of AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than venue of AGM (Remote e-voting).

The Remote e-voting shall commence on **Thursday, 24th day of September, 2026 (9:00 AM IST) and end on Sunday, 27th day of September, 2026 (5:00 PM IST).**

Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses are provided in the Notice to the members.

Members may please note that in terms of aforementioned Circulars, the Company will not be sending physical copies of AGM Notice and Annual Report to the Members.

As per Saksham Niveshak campaign the company hereby inform to its shareholders who has there unclaimed / unpaid dividend shall process with the IEPF Authority and the company. And who have not updated their KYC records are requested to update the same through their Depository Participants at the earliest.

For, Rushil Decor Limited
Sd/-
Hasmukh K. Modi
Company Secretary

Date: 20.08.2026
Place: Ahmedabad

VIR
LAMINATE | MDF | PVC | PLY

तो एनएसई पर भी खरीद-बेच सकेंगे एनएसई के शेयर!

एजेंसियां
नई दिल्ली, 20 अगस्त

अपने प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के बाद नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) अपने प्लेटफॉर्म पर खुद के शेयरों के कारोबार की अनुमति दे सकता है। इसके लिए उसे सेबी से अलग से मंजूरी नहीं लेनी होगी। प्रस्तावित व्यवस्था एक्सचेंज के मौजूदा 'परमिटेड-टु-ट्रेड' रूट के तहत आएगी। मामले के जानकार उद्योग के एक सूत्र ने यह जानकारी दी।

यह विभेद इसलिए जरूरी है कि परमिशन-टु-ट्रेड लिस्टिंग जैसा नहीं होती है। एक सूचीबद्ध कंपनी को अपने प्राथमिक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर करना होता है और उसकी अनुपालन की भी जिम्मेदारी होती है। परमिशन-टु-ट्रेड फ्रेमवर्क सिर्फ निवेशकों को दूसरे एक्सचेंज पर शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता है।

'परमिटेड-टु-ट्रेड' फ्रेमवर्क के तहत कोई भी एक्सचेंज किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयरों में ट्रेडिंग की अनुमति दे सकता है। घटनाक्रम से अवगत एक अधिकारी ने कहा, 'एनएसई को अपने प्लेटफॉर्म पर अपने स्वयं के शेयरों में ट्रेड करने की अनुमति देने के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत नहीं हो सकती है।'

एनएसई के पास पहले से ही 200 से अधिक कंपनियां हैं जिनके शेयर उसके प्लेटफॉर्म पर कारोबार करते हैं, लेकिन उस पर सूचीबद्ध नहीं हैं। इससे जाहिर होता है कि किसी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि वह प्रतिभूति वहां सूचीबद्ध है।

यही व्यवस्था अन्य एक्सचेंज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एमएसईआई और एनसीडीईएक्स के पास मिलाकर लगभग 4,000 कंपनियां हैं जिनके शेयरों को उनके प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने की अनुमति है, जबकि वे उन एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं हैं।

ऐसी 'परमिटेड-टु-ट्रेड' व्यवस्थाओं में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए सेबी से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रतिभूतियों के कारोबार से संबंधित है और नई लिस्टिंग जैसी नहीं है।

यह कदम एनएसई के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वह अपनी सूचीबद्धता की तैयारी कर रहा है। अगर एनएसई अपने शेयरों को किसी अन्य एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराता है, तो मौजूदा फ्रेमवर्क के तहत उन शेयरों को संभावित रूप से एनएसई पर ट्रेड करने की अनुमति दी जा सकती है।

OBCL Limited

OBCL Limited

(पूर्व में Orissa Bengal Carrier Limited के नाम से जाना जाता था),
CIN: L63090CT1994PLC008732
रजिस्टर्ड ऑफिस: जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) 492001,
कॉर्पोरेट ऑफिस: ए-1, तीसरी मंजिल, सीजी एलीट कॉम्प्लेक्स,
मंडी गेट के सामने, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) 492001 वेबसाइट: www.obclimited.com,
ईमेल : cs@obclimited.com | दूरभाष: +91-771 2281321 / 0771-4054518

वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की **31वीं वार्षिक सामान्य बैठक, दिन- बुधवार, दिनांक- 16 सितम्बर 2026** को प्रातः 11:00 बजे एजीएम बुलाने के नोटिस में बताए गए व्यवसायों का संचालन करने के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय ए-1, तीसरी मंजिल, सीजी एलीट कॉम्प्लेक्स, मंडी गेट के सामने, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)- 492001 में कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में भौतिक विधि द्वारा आयोजित की जाएगी।

वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) अनुसूची का विवरण

क्र.	विवरण	अनुसूची
1	मतदान में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों की सूची निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख	09 सितम्बर, 2026
2	नोटिस के प्रेषण के पूरे होने की संभावित तिथि।	22 अगस्त 2026
3	ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि	11 सितम्बर, 2026 प्रातः 11:00 बजे से
4	ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि	15 सितम्बर, 2026 शाम 05:00 बजे तक
5	संवीक्षक	मेसर्स अनिल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
6	संवीक्षक द्वारा मतदान पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावित तिथि	18 सितम्बर, 2026
7	मतदान परिणामों के विषय में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देने और उसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रविष्ट करने की संभवित तिथि।	18 सितम्बर, 2026

सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस सभी शेयरधारकों को जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी को अपने डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है उन्हें अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उन्हें भौतिक रूप से नोटिस भेजा जा रहा है। एजीएम की सूचना व 31वीं वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों बीएसई- **www.bseindia.com** और एनएसई- **www.nseindia.com** पर एवं कंपनी की वेबसाइट **www.obclimited.com** पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के संशोधित नियम 20 के साथ पठित प्रावधान के अनुसार, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। दूरदराज से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया के विवरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस की निर्देश के तरफ ध्यान दें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के माध्यम से या वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:-

1) सदस्य ऊपर लिखित तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा; 2) एक बार सदस्य द्वारा किसी रेजोल्यूशन पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी; 3) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे; 4) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट पर प्रविष्ट कर दिए जाएंगे; तथा 5) यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी जी से 022-23058738 या 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग टोल फ्री नंबर है -1800225533. एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.obclimited.com** से डाउनलोड की जा सकती है

दिनांक- 20.08.2026
स्थान- रायपुर

कृते, ओबीसीएल लिमिटेड
एसडी/- रवि अग्रवाल, प्रबंध निदेशक

कॉपटॉल और मानसी ने कैसे की हेरफेर

पृष्ठ 1 का शेष

बाजार नियामक सेबी ने बताया है कि फर्म की रणनीतियों जिन्हें सिंथेटिक लॉन्ग ऐसेट पोजीशन या कृत्रिम कारक कहा जाता है, के तहत सेंसेक्स में बढ़त से कॉपटॉल को काफी मुनाफा हो सकता था।

उसी दिन एक अन्य कंपनी मानसी शेयर ऐंड स्टॉक ब्रोकिंग ने शुरुआती बढ़त के बाद सेंसेक्स की 8 कंपनियों के शेयरों में संदर्भ मूल्य से लगभग 2.5 फीसदी कम कीमत पर काफी बिक्री ऑर्डर दिए। कंपनी ने एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स वायदा वा अपनी बकाया पोजीशन से फायदा उठाने के लिए ये ऑर्डर दिए और बाद में उन्हें रद्द भी कर दिया। इससे लगभग चार से पांच मिनट तक सेंसेक्स का आईईपी नीचे आ गया।

नियामक ने स्पष्ट किया है कि दोनों संस्थाओं ने आपस में मिलकर यानी 'सांठगांठ' करके काम नहीं किया था। दोनों ने स्वतंत्र रूप से एक जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर बाजार में हेरफेर किया। सेबी ने इन संस्थाओं को शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है और गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को जब्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही, सेबी के चेयरमैन ने बाजार में हेरफेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड की ओर से भेजे गए ईमेल पर जेपी मॉर्गन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, मानसी के सीईओ को भेजे गए ईमेल का खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला था। हालांकि, इस तरह की घटनाओं ने बाजार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वे सीएएस व्यवस्था में कुछ बदलाव करने की मांग कर रहे हैं।

सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज नियामक की पहली निगरानी कड़ी होते हैं ऐसे में संदिग्ध और बाजार में हेरफेर वाले सौदों की पहचान सबसे पहले एक्सचेंज को ही करनी चाहिए थी।

एक अन्य नियामकीय विशेषज्ञ ने कहा कि सेबी का यह आदेश बाजार से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा संकेत है कि नियामक की नजर बाजार की गतिविधियों पर बनी हुई है।

मुंबई | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 बिज़नेस स्टैंडर्ड

होगा 10 लाख टन चीनी का आयात

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 20 अगस्त

देश में महंगी बिकती चीनी का असर

- 19 अगस्त, 2026 को भारत के प्रमुख बाजारों में चीनी की हाजिर कीमत 5530 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई, जो 16 साल का उच्च स्तर है
- चीनी की खुदरा कीमत 18 अगस्त को सालाना आधार पर करीब 13 प्रतिशत बढ़कर 52.30 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात बगैर शुल्क करने की इजाजत दे दी गई है। भारत को करीब 10 साल के बाद चीनी आयात करना पड़ रहा है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक चीनी का आयात 31 अक्टूबर, 2026 तक ही किया जा सकेगा। इस तरह शुल्क मुक्त आयात के लिए दो महीने से कुछ ज्यादा वक्त मिलेगा, जब त्योहारों की वजह से देश में चीनी की सबसे ज्यादा खपत होती है। भारत में गन्ने की पेराई नवंबर से शुरू होती है।

व्यापार और उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस अधिसूचना में एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस) के तहत आयात की गई चीनी को एक बार शुल्क दर कोटा योजना में भी बदला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसका मतलब यह है कि चीनी मिलें आयात की गई कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर देश में बेच सकती हैं, जबकि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत उन्हें ऐसा करने की मनाही होती है।

इस स्कीम के तहत चीनी मिलों को आयात की गई चीनी के बराबर मात्रा में सफेद या रिफाइन्ड चीनी तय मियाद के भीतर निर्यात करनी ही पड़ती है। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इसका साफ मतलब है कि चीनी मिलें आयात की गई कच्ची चीनी को देसी बाजार में बेच सकती हैं और सजा या जुर्माना झेले बगैर चीनी की उपलब्धता बढ़ा सकती हैं।'

इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रीय निदेशक दिलीप पाटिल ने कहा कि कम अवधि के लिए लाई गई इस नीति का मकसद देसी बाजार में आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों पर अंकुश कसना लगता है। इस पर आयात शुल्क के नुकसान की भरपाई जीएसटी वसूलकर हो जाएगी और अंतिम उत्पाद भी उत्पाद देश के भीतर ही रहेगा।

एनसीडीईएक्स के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के प्रमुख बाजारों में 19 अगस्त, 2026 को चीनी की हाजिर कीमत 5,530 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, जो 16 साल में सबसे ऊंचा हाजिर भाव है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि चीनी की खुदरा कीमत 18 अगस्त को 52.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो 18 अगस्त, 2025 को 46.34 रुपये प्रति किलो थी। चीनी की मांग आम तौर पर अगस्त और नवंबर के बीच बढ़ती है क्योंकि इसी बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे महत्त्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं।

इस बीच केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए भंडारण सीमा लागू कर कथित जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती जारी रखी है। सरकार ने सभी मिलों से ब्योरा मांगते हुए पूछा है कि 17 से 19 अगस्त के बीच किस मिल ने कितनी चीनी बेची और किस ग्राहक ने कितनी चीनी खरीदी। खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि हर महीने 10 टन से अधिक चीनी इस्तेमाल करने वाले थोक उपभोक्ता 15 दिनों की खपत से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

खाद्य मंत्रालय ने चीनी (थोक उपभोक्ताओं के पास स्टॉक की सीमा) आदेश, 2026 अधिसूचित कर दिया है, जिसके दायरे में कन्फेक्शनरी, शीतल पेय निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मिठाई विक्रेता और अन्य संस्थागत खरीदार शामिल हैं। यह आदेश 1 सितंबर से प्रभावी होगा और 30 नवंबर तक लागू रहेगा।

इधर केंद्र द्वारा चीनी के भंडारण की सीमा घटाए जाने की खबर और देश-दुनिया में चीनी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने की खबर से चीनी कंपनियों के शेयर दौड़ पड़े।

हालांकि 10 साल बाद चीनी के शुल्क मुक्त आयात की इजाजत मुख्य रूप से देसी बाजार में इसकी बढ़ती कीमतों की वजह से ही मिली है। किंतु कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश में चीनी की किल्लत की आशंका के बाद भी उत्पादन के गलत अनुमानों के आधार पर 15 से 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का चूक भरा फैसला भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

भारत ने नवंबर 2025 में ही 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी थी, जिसे बाद में 5 लाख टन और बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया था। उद्योग के अनुमान हैं कि इसमें से लगभग 8 लाख टन चीनी देश से बाहर भेज दी गई है। अब लगभग उतनी ही कच्ची चीनी आयात करनी पड़ रही है।

कुछ अनुमानों के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए 2025-26 सीजन में एथनॉल बनाने के लिए 24 लाख टन चीनी अलग करने के बाद भारत का वास्तविक शुद्ध चीनी उत्पादन लगभग 279 लाख टन है। 2025-26 का सीजन शुरू होने पर देश में 47 लाख टन चीनी का भंडार था। इसका मतलब है कि कुल 326 लाख टन के करीब चीनी उपलब्ध होगी। इस साल चीनी की खपत 280 लाख टन रहने का अनुमान है। इस तरह सीजन खत्म होने पर देश में 47 लाख टन चीनी का भंडार होगा। मगर जैसे ही 8 लाख टन का निर्यात आंकड़ा घटाते हैं तो भंडार 35 से 39 लाख टन ही रह जाता है और देश में चीनी की किल्लत का खटका हो जाता है।

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा, 'आयात की वजह से कीमते घटने पर मिलों के लिए दिक्कत नहीं होगी।'

तीसरे पक्ष के स्रोतों से एथनॉल खरीद पर लगा प्रतिबंध

भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी एथेनॉल आपूर्तिकर्ता स्वदेशी विनिर्माता होने चाहिए, जो अपनी पंजीकृत डिस्टिलरी इकाइयों के मालिक हों। प्रमुख सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के एक गठबंधन की ओर से बीपीसीएल द्वारा जारी इस नोटिस में स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष के स्रोतों से एथेनॉल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जुलाई में बुनियादी क्षेत्र की वृद्धि गिरकर 5.4 प्रतिशत

हिमांशी भारद्वाज
नई दिल्ली, 20 अगस्त

नौ बुनियादी क्षेत्रों में से पांच क्षेत्रों का जुलाई में खराब प्रदर्शन।

भारत के नौ बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि जुलाई में सुस्त होकर 5.4 प्रतिशत हो गई जबकि जबकि यह जून में संशोधित होकर 6 प्रतिशत थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के गुरुवार को जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार नौ बुनियादी क्षेत्रों में से पांच क्षेत्रों ने पिछले महीने की तुलना में जुलाई में खराब प्रदर्शन किया।

यह नई श्रृंखला का दूसरा आंकड़ा था और इसका आधार वर्ष 2022-23 है। इसने पुरानी 2011-12 की श्रृंखला की जगह ली। इसमें लौह अयस्क को शामिल किया गया और बुनियादी क्षेत्रों की संख्या आठ से बढ़कर नौ हो गई। जुलाई में कुल सूचकांक बढ़कर 121.2 हो गया, जो पिछले महीने 120.7 था। इस सूचकांक में बिजली का सबसे ज्यादा भारांश (30.9 प्रतिशत) है। उसकी वृद्धि दर पिछले महीने के 11.4 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गई।

नौ-क्षेत्रों वाले सूचकांक में 4.9 प्रतिशत भारांश लौह अयस्क है और यह मुख्य आंकड़ों में सुस्ती का सबसे बड़ा कारण रहा। इसकी वृद्धि जून के 44.5 प्रतिशत से घटकर जुलाई में 29.5 प्रतिशत (आधे से भी कम) रह गई। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'अकेले इसी ने पिछले महीने की तुलना में जुलाई में बुनियादी क्षेत्र के आउटपुट के आंकड़ों पर 95 आधार अंक का दबाव डाला।'

आंकड़ों से पता चला कि महीने के दौरान नौ में से छह क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इनमें लौह अयस्क, बिजली, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद और कोयला सकारात्मक दायरे में रहे। हालांकि प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और उर्वरक में गिरावट आई। खास बात यह है कि रिफाइनरी उत्पादों का सूचकांक में दूसरा सबसे बड़ा भारांश है। इन उत्पादों ने अपनी चाल बदली और लगातार तीन महीने की गिरावट के बाद रेड जोन से बाहर आ गए। इस क्षेत्र में जून में 4 प्रतिशत की गिरावट के बाद जुलाई में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह नौ महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान कुल मिलाकर सूचकांक में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.5 प्रतिशत थी। सीमेंट का उत्पादन 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 13.1 प्रतिशत (सात महीने का सबसे ऊंचा स्तर) हो गया और कोयले का उत्पादन जून के 1.4 प्रतिशत के मुकाबले तेजी से बढ़कर 7.6 प्रतिशत (11 महीने का सबसे ऊंचा स्तर) हो गया।

नायर ने कहा, 'जून 2026 में मॉनसून की भारी कमी के कारण विनिर्माण गतिविधि लंबे समय तक चलने के बाद इन्वेंट्री को फिर से भरने से जुलाई, 2026 में सीमेंट प्रोडक्शन को मदद मिलने की संभावना है।' दूसरी ओर स्टील में ग्रोथ जुलाई में 2.9 प्रतिशत रही, जो जून के 5.6 प्रतिशत से कम है। जुलाई में गिरावट वाले दायरे में रहने वाले क्षेत्रों में कच्चा तेल और उर्वरक में गिरावट और अधिक हो गई। यह कच्चे तेल में 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.3 प्रतिशथ और उर्वरक में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई।

सवाल जवाब

राज्यों के हितों की रक्षा के लिए कोल इंडिया प्रतिबद्ध

कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी साईराम मानते हैं कि हम खनिज वाले राज्यों के वैध राजस्व हितों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। एमएमडीआर संशोधन अधिनयम से कोयला परियोजनाओं की अनिश्चितता दूर होगी और ज्यादा निवेश आएगा। साकेत कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोयले की कीमत बढ़ने का असर आखिरकार बिजली दरों पर पड़ता है। प्रमुख अंश...

देश की सबसे बड़ी खनन कंपनी के तौर पर आप खनिज और धातु विकास और विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम 2026 के प्रावधानों को कैसे देखते हैं?

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक भुगतानों के माध्यम से राज्य के राजस्व में बड़ा योगदान करने वालों में से एक है। हम खनिज वाले राज्यों के वैध राजस्व हितों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। साथ ही, कोयला खनन जैसे पूंजी केंद्रित और लंबी अवधि वाले क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित या पूर्वव्यापी लेवी की वजह से परियोजना को लेकर अनिश्चितता होती है। एक स्थिर और अनुमानित कराधान ढांचा होने से निवेश, क्षमता विस्तार और घरेलू कोयले की विश्वसनीय आपूर्ति को समर्थन मिलेगा। इससे न केवल व्यापक अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान होगा, बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भी सुधार होगा।

रॉयल्टी, डीएमएफ और राज्य-विशिष्ट लेवी जैसे वैधानिक भुगतानों के रूप में सीआईएल कितना भुगतान करती है?

सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने 2025-26 के दौरान राज्यों को रॉयल्टी, डीएमएफ, राज्य जीएसटी, उपकर और लेवी सहित 32,000 करोड़ रुपये से अधिक वैधानिक लेवी का भुगतान किया। कंपनी ने 2025-26 में रॉयल्टी के रूप में 15,950 करोड़ रुपये, डीएमएफ के लिए 4,750 करोड़ रुपये, एसजीएसटी के लिए 2,320 करोड़ रुपये और सेस के रूप में 2,222 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक था। इसके अतिरिक्त लगभग 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान राज्यों से जुड़े अन्य लेवी के लिए किया गया, जिसमें झारखंड को 4,888 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 1,375 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 575 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 92 करोड़ रुपये और ओडिशा को 10 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।

संशोधित कानून से कोल इंडिया को कितनी वित्तीय राहत मिल सकती है?

इसे लाभ या हानि के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। कोल इंडिया उन राज्यों के आर्थिक विकास को समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें वह काम करती है। एक स्थिर और अनुमानित कराधान ढांचा कारोबार के सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देगा और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसके बदले में, खनिज उत्पादन में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे।

क्या आप मानते हैं कि राज्य स्तर पर असमान लेवी से कोयले की लागत बढ़ती है। अंततः बिजली महंगी होती है?

रॉयल्टी, डीएमएफ और जीएसटी कोयला आपूर्ति से जुड़ी वैधानिक लागत संरचना के प्रमुख घटक हैं। जब अतिरिक्त या अलग लेवी लगाई जाती हैं, तो कोयले की डिलीवरी लागत बढ़ जाती है। बिजली क्षेत्र के लिए कोयला प्रमुख इनपुट लागत है। इसलिए कोयले की लागत में किसी भी वृद्धि का असर बिजली उत्पादन की लागत पर पड़ता है और नियामक ढांचे के मुताबिक बिजली की दरों पर असर पड़ सकता है।

अगर संशोधन से अधिक समान लेवी ढांचा बनता है, तो सीआईएल कोयले की कीमतें घटाएगा या मार्जिन सुधारेगा?

फाइनैंशियल स्टेटमेंट में लेवी को व्यय में शामिल किया जाता है। जब इसकी लागत का बोझ ग्राहकों पर डाला जाता है तो यह हमें वापस मिल जाता है। ऐसे में लेवी में किसी भी बदलाव से सीआईएल के मार्जिन पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। आमतौर पर इसे ग्राहकों से वसूला जाता है।

क्या संशोधित राजकोषीय ढांचा सीआईएल के निवेश निर्णयों, खदान विकास योजनाओं या नई खदानों की अर्थशास्त्र को बदलेगा?

कोल इंडिया व्यापक मानदंडों की सूची को देखने के बाद खदान विकसित करने का फैसला करती है। कोल इंडिया की बड़ी खदान में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, खदान अवसंरचना, कोयला निकासी अवसंरचना और खनन के बड़े उपकरणों पर अग्रिम व्यय शामिल होता है। खनन परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निवेश का फैसला किया जाता है। कोयला से बिजली के मूल्य की श्रृंखला में अधिक निश्चितता से इस क्षेत्र के निरंतर आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका के बेहतर साधन मिलेंगे और समग्र कल्याण में इसका अहम योगदान होगा।

भारत व सिंगापुर के बीच दूरसंचार, समुद्री विरासत में सहयोग के समझौते

भाषा
सिंगापुर, 20 अगस्त

भारत और सिंगापुर ने गुरुवार को दूरसंचार एवं प्रसारण, समुद्री विरासत और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक (आईएसएमआर) के दौरान दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि एक आशय पत्र (एलओआई) का आदान-प्रदान हुआ।

बैठक में उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, संपर्क, डिजिटल, वित्तीय प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों में समुद्री विरासत, खाद्य सुरक्षा और दूरसंचार एवं प्रसारण नियमन के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि ये समझौते आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेंगे।

सिंगापुर में चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद।

सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग ने किया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय मंत्री के. षणमुगम, विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोसेफिन तेओ तथा परिवहन मंत्री जेफ्री सिओ भी शामिल हुए।

चौथी आईएसएमआर बैठक में उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता समेत छह प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और नए अवसर तलाशे गए। बैठक में भारत-सिंगापुर साझेदारी में जारी तेजी को रेखांकित किया गया और इसे ठोस परिणामों में बदलने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि दोनों पक्षों ने उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, संपर्क, डिजिटल, कौशल विकास और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।

दिल्ली में 2047 तक बनेंगे 40 लाख नए मकान

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को 'दिल्ली मास्टर प्लान 2047' जारी करते हुए कहा कि शहर में करीब 40 लाख नए घर बनाए जाएंगे और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2047 तक मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार कर 695 किलोमीटर किया जाएगा।

मनोहर लाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल टी. एस. संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली की आबादी बढ़कर 3.20 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे विकास पर दबाव बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में शहर का तेजी से विकास सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही यमुना के 180 वर्ग किलोमीटर बाढ़ क्षेत्र और रिज क्षेत्र का संरक्षण भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 से 40 लाख नए फ्लैट बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि शहर में मेट्रो रेल, बसों और छह नए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) गलियारों समेत सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। *भाषा*

बीएस सूडोकू 5672

			2					
		5		7	8		2	6
7							3	
6								
				3	9	7		
		8	5		2			
1	4							2
			8				4	
8				6	5		7	3

परिणाम संख्या 5671

2	1	7	4	5	6	8	3	9
4	3	6	7	9	8	1	2	5
9	8	5	2	3	1	4	6	7
8	5	9	1	2	3	6	7	4
3	6	2	9	7	4	5	8	1
7	4	1	8	6	5	3	9	2
1	7	4	3	8	2	9	5	6
5	2	3	6	4	9	7	1	8
6	9	8	5	1	7	2	4	3

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

दिल्ली में 2027 से नए एलजीवी वाहनों पर रोक

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 20 अगस्त

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयुक्त (सीएक्यूएम) ने अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के कुल 3.5 टन वजन के हल्के माल ढोने वाले नए वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इन्हें 'एन1 वाहन' की श्रेणी में रखा गया है। यह जानकारी सीएक्यूएम ने आज दी।

बहरहाल, 3-7.5 टन वजनी गैर इलेक्ट्रॉनिक एलजीवी वाहनों को 'एन 2 वाहनों' की श्रेणी में रखा गया है। इन वाहनों पर 1 जनवरी, 2028 से रोक होगी। सीएक्यूएम का यह आदेश 19 अगस्त को जारी किया गया था। यह दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति से कहीं आगे का कदम है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 30 जून को अधिसूचित की थी। इसमें दिल्ली सरकार ने यह अनिवार्य किया था कि 1 जनवरी, 2027 से केवल इलेक्ट्रिक एन1 एलजीवी का ही नया पंजीकरण हो सकेगा, वहीं उसने गैर-इलेक्ट्रिक एन2 एलजीवी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई थी। हालांकि सीएक्यूएम ने एन2 वाहनों को भी इस रोक के दायरे में शामिल कर लिया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयुक्त ने वाहनों पर रोक लगाई।

इस आदेश का असर गैर-इलेक्ट्रिक एन 1 और एन 2 वाणिज्यिक वाहनों के बड़े निर्माताओं जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, मारुति सुज़ुकी और वीई कमर्शियल व्हीकल्स पर पड़ेगा। दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में उनके पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मॉडल धीरे-धीरे नए पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

वैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड (अपनी सब्सिडियरी स्विच मोबिलिटी के जरिए) और वीई कमर्शिल व्हीक्लस जैसी कंपनियां एन1 खंड में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ मौजूद हैं।

यूलर मोटर्स जैसे इलेक्ट्रिक एलजीवी स्टार्टअप्स की भी एन 1 मार्केट में अच्छी-खासी हिस्सेदारी है। आयुक्त ने कहा कि नौ रजिस्टर्ड वाहन निर्माता अभी 20 इलेक्ट्रिक एन 1 मॉडल बेच रहे हैं। ये पाबंदियों के पहले चरण के लिए पर्याप्त उत्पाद देते हैं। एन 2 वाहनों के मामले में इसने ज्यादा सावधानी बरती क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक मार्केट शुरुआती दौर में है। सीएक्यूएम ने देखा कि 2025 में दिल्ली-एनसीआर में 2,744 एन 2 एलजीवी नए पंजीकृत हुए लेकिन उनमें से एक भी इलेक्ट्रिक नहीं था। इसने कहा कि चार वाहन निर्माताओं के पास छह इलेक्ट्रिक एन 2 मॉडल उपलब्ध थे।

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 19 अंक 159

बदलती अपेक्षाएं

भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने इस माह के आरंभ में अपनी बैठक में नीतिगत रीपो दर को अपरिवर्तित रहने देने का निर्णय लिया था। वह समझदारी भरा निर्णय था। हालांकि जून में मुद्रास्फीति की दर तय लक्ष्य को पार कर गई थी लेकिन लगातार 16 महीनों तक वह लक्ष्य से नीचे भी रही। इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मोर्चों पर स्पष्टता की प्रतीक्षा भी समझदारी भरी बात रही। पश्चिम एशिया के हालात में कोई खास सुधार होता नहीं दिख रहा है और कच्चे तेल की कीमतें लगातार उतार-चढ़ाव दर्शा रही हैं। उसकी निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। अगली बैठक तक कृषि उत्पादन पर कमजोर मॉनसून के संभावित असर को लेकर भी और अधिक स्पष्टता आएगी। बहरहाल, जैसा कि इस समाचार पत्र ने भी कहा, रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान यह सुझाते हैं कि नीतिगत दर लंबे समय तक मौजूदा स्तर पर नहीं रहेगी। बैठक का ब्योरा बुधवार को जारी किया गया और उसकी व्याख्या भी कमोबेश इसी तर्ज पर की जा रही है।

इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दलील दी कि व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि और अपेक्षाओं के असंतुलन को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'यदि इन जोखिमों के वास्तविक होने के कोई प्रमाण मिलते हैं तो नीतिगत सख्ती की आवश्यकता पड़ सकती है।' डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने और स्पष्ट रूप से कहा, 'वर्तमान समय में किसी भी अतिरिक्त नरमी की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। बल्कि, यह देखते हुए कि समग्र मुद्रास्फीति 2026-27 की तीसरी तिमाही में 5.9 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है, वर्ष के दौरान दर वृद्धि का मामला बन सकता है।' वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति अनुमान 10 आधार अंक घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया। यद्यपि दर के वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही से शुरू होकर लगातार तीन तिमाहियों तक 5 फीसदी से ऊपर रहने का अनुमान है। 2027-28 की पहली तिमाही से आगे के अनुमानों को देखना दिलचस्प होगा। अधिक स्पष्टता संभवतः अक्टूबर में होने वाली अगली एमपीसी बैठक और अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट के जारी होने पर सामने आएगी।

वर्तमान स्थिति में मूल्य दबाव बढ़ने का अनुमान है। हेडलाइन यानी समग्र मुद्रास्फीति के 5 फीसदी से ऊपर जाकर तीसरी तिमाही में 5.9 फीसदी तक पहुंचने की आशंका है। इस स्थिति में 5.25 फीसदी की नीतिगत रीपो दर वास्तविक रूप से ऋणात्मक हो जाएगी। यह अवांछनीय है। रिजर्व बैंक का उद्देश्य यह है कि वास्तविक नीतिगत दर ऋणात्मक क्षेत्र में न जाए। खासकर तब जब वृद्धि जोखिम में न हो। इसलिए नीतिगत दरों में समायोजन आवश्यक होगा। आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि एमपीसी अक्टूबर में सख्ती शुरू करेगा या कुछ समय और प्रतीक्षा की गुंजाइश होगी। अगले वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान निर्णायक होंगे। ध्यान देने योग्य है कि मौद्रिक नीति का असर विलंब से होता है, और यदि दर अगले वित्तीय वर्ष में ऊंची रहने की उम्मीद है, तो सख्ती अक्टूबर से ही शुरू हो सकती है।

हालांकि भारत में मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के विकास से संचालित नहीं होती लेकिन मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए किए गए नीतिगत समायोजन इसमें मदद कर सकते हैं। उच्च मुद्रास्फीति दर और अधिक राजकोषीय घाटे की चिंताओं के कारण विकसित बाजारों में यील्ड बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका सरकार ने यील्ड कम करने के लिए बॉन्ड पुनर्खरीद बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में 30-वर्षीय अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड 5.3 फीसदी से ऊपर चली गई, जो 2007 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। यील्ड में कम अंतर विकसित देशों से उभरते बाजारों में ऋण पूंजी प्रवाह को हतोत्साहित करता है। हालांकि कम से कम निकट भविष्य में, भारत मुद्रा मोर्चे पर बेहतर स्थिति में है। रिजर्व बैंक द्वारा घोषित स्वैप व्यवस्था के माध्यम से पर्याप्त धन जुटाया जा रहा है। फिर भी नीतिगत दरों में समायोजन ऋण प्रवाह में मदद कर सकता है।

अजय मोहंती

ईएसजी खुलासे को सार्थक बनाने की आवश्यकता

भारत को अपने ईएसजी रिपोर्टिंग मानकों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानकों के अनुरूप बनाने की जरूरत है ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके। बता रहे हैं अजय त्यागी

पांच वर्ष पहले 2021 में जब बाजार नियामक ने 2022-23 से भारत में सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के लिए कारोबार जवाबदेही एवं स्थायित्व रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) खुलासों को अनिवार्य बनाया था तब इसे कंपनियों द्वारा गैर वित्तीय प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया था। इस मामले में भारत अग्रणी देशों में शामिल था। यहां तक कि यूरोपीय संघ ने भी ऐसा खुलासा 2024-25 में अनिवार्य किया था।

वर्ष 2023 में बीआरएसआर कोर की प्रस्तुति के बाद यह और अधिक मजबूत हुआ। उसमें मुख्य प्रदर्शन संकेतकों यानी केपीआई का तीसरे पक्ष द्वारा आकलन अनिवार्य किया गया जिससे योजना की विश्वसनीयता बढ़ी।

बीआरएसआर दिशानिर्देशों की समीक्षा वैश्विक विकास के अनुरूप लगातार होती रहनी चाहिए ताकि वे हितधारकों के लिए प्रासंगिक बने रहें। बीआरएसआर दिशानिर्देश सूचीबद्ध कंपनियों को ईएसजी के अंतर्गत नौ श्रेणियों में जानकारी का खुलासा करने को बाध्य करते हैं। वर्तमान में रिपोर्टिंग प्रारूप क्षेत्र निरपेक्ष हैं। इन्हें क्षेत्र विशिष्ट प्रारूप में बदलना आवश्यक है। निश्चित रूप से ताप बिजली संयंत्र के लिए प्रारूप आईटी उद्योग के समान नहीं हो सकते। मौजूदा दिशानिर्देश कंपनियों को उन कॉलमों में 'लागू नहीं' लिखने की अनुमति देते हैं जो उनके लिए प्रासंगिक नहीं हैं लेकिन इससे या तो सूचना का बोझ बढ़ सकता है या क्षेत्र-विशिष्ट जानकारी की कमी हो सकती है। नियामक राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत कर सकता है और क्षेत्र-विशिष्ट टेम्पलेट निर्धारित कर सकता है।

प्रकटीकरण व्यवस्था हितधारकों को एक ही क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की तुलना करने में मदद करती है। यह और उपयोगी होगा यदि अलग-अलग पैमानों पर दी गई जानकारी की तुलना सरकार या नियामकों द्वारा अलग-अलग गतिविधियों के लिए तय किए गए बेंचमार्क से भी की जा सके। बेंचमार्किंग के अभाव में किसी कंपनी के असल प्रदर्शन का आकलन करना संभव नहीं है। सरकार के पास ईएसजी के विभिन्न तत्त्वों के अंतर्गत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और घरेलू आकांक्षाएं हैं। उसे यह तय करना होगा कि इन प्रतिबद्धताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में वह कंपनियों से किस प्रकार का योगदान अपेक्षित करती है।

उदाहरण के लिए ईएसजी के पर्यावरणीय घटक के अंतर्गत सरकार ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 फीसदी तक कम करने और 2070 तक विशुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है।

स्वाभाविक रूप से ये लक्ष्य तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक इन्हें विभिन्न गतिविधियों और क्षेत्रों में विभाजित कर प्रगति की निगरानी न की जाए। सरकार कंपनियों से क्या अपेक्षा करती है? हाल ही में, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत उन सेक्टरों के लिए कुछ सेक्टर-विशिष्ट जीएचसी उत्सर्जन लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें उत्सर्जन कम करना मुश्किल है। इन क्षेत्रों की कंपनियों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने प्रदर्शन को इन लक्ष्यों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उजागर करें।

दरअसल ऐसे लक्ष्य और अधिक क्षेत्रों के लिए तय किए जाने चाहिए और प्रदर्शन की निगरानी होनी चाहिए। आगे चलकर अन्य मानकों जैसे जल-उपयोग गहनता और कुल ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात के लिए भी विशिष्ट लक्ष्य तय किए जाने चाहिए।

बीआरएसआर का दायरा केवल शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यद्यपि बाजार पूंजीकरण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण करना एक सरल मानदंड है लेकिन इससे अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उदाहरण के लिए जीएचजी का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले कुछ उद्योग शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां जिनके ईएसजी संबंधी प्रकटीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं वे सूचीबद्ध होने के बजाय गैर-सूचीबद्ध रहना पसंद करती हैं।

इसलिए बीआरएसआर के लिए अपनाए गए मानदंडों पर पुनर्विचार करने और इसके दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कंपनियों के निदेशक मंडलों में ईएसजी से जुड़े मामलों के लिए कोई अलग समिति नहीं होती। सामान्यतः इन विषयों को सीएसआर समिति या जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से देखा जाता है। ऐसे में जिन कंपनियों के लिए ईएसजी का विशेष महत्त्व है, उनमें ईएसजी मामलों के लिए एक अलग बोर्ड समिति का गठन नियामक द्वारा अनिवार्य किया जाना चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी बीआरएसआर के दायरे में लाना आवश्यक होगा, विशेष रूप से वे एमएसएमई जो पहले से शामिल कंपनियों की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जानी चाहिए।

सरकारी स्तर पर ईएसजी के विभिन्न तत्त्वों के अंतर्गत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और घरेलू आकांक्षाएं हैं। इन लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए भविष्य में हमें विदेशी वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा चाहिए होगा। इस पर सलाहकार संगठनों, उद्योग समूहों और शोधकर्ताओं के बीच आम सहमति है। कई विदेशी पेंशन फंड, सॉवरिन वेल्थ फंड और अन्य दीर्घकालिक निवेश फंड के निवेशकों को यह निर्देश होता है कि वे अपनी पूंजी का एक हिस्सा केवल सतत विकास परियोजनाओं में लगाएं। भारत में निवेश करने के लिए वे अपेक्षा करेंगे कि भारतीय कंपनियां उन्हीं मानकों का पालन करें जो उनके अपने क्षेत्रों में लागू होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्थायित्व मानक बोर्ड (आईएसएसबी) द्वारा विकसित टिकाऊ रिपोर्टिंग मानक जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के अंतर्गत आता है उसे वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और अधिकाधिक क्षेत्र इन्हें अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत को सभी हितधारकों से परामर्श कर एक रोडमैप तैयार करना चाहिए ताकि बीआरएसआर को इन मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो और सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

शहरी सहकारी बैंक: अधूरा अतीत, उभरता वर्तमान

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

बाइस साल के अंतराल के बाद भारतीय रिजर्व बैंक नए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ऑन-टैप लाइसेंसिंग का रास्ता खोलने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने इसके लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि लाइसेंस किसी निर्धारित समय वाले विंडो की जगह हर समय लगातार दिए जाएंगे। इन मानकों के तहत पात्र विविध राज्य ऋण सहकारी समितियां जिनके पास कम से कम 10 साल के संचालन का रिकॉर्ड हो और न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये की जमा राशि तथा 300 करोड़ रुपये की हैसियत हो, वे यूसीबी में रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।

यह ऐसे समय पर हो रहा है जब रिजर्व बैंक यूसीबी के लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक बदलाव को प्रोत्साहित कर रहा है। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पहला ऐसा यूसीबी है जो सफलतापूर्वक रूपांतरित हुआ। एक अन्य बड़ा यूसीबी नियामकीय बचाव अभियान के माध्यम से एसएफबी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। घोटाले से प्रभावित पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) का विलय कर उसे यूनिटी स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया। इतिहास पर नजर डालें तो भारत की पहली ऋण सहकारी समिति 1903 में बंगाल में स्थानीय सरकार के समर्थन से बनी थी और इसे ब्रिटिश सरकार के फ्रेंडली सोसाइटीज ऐक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसके बाद 25 मार्च, 1904 को भारत का सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू किया गया।

1911 तक 5,300 समितियां थीं जिनकी संयुक्त सदस्यता 3 लाख से अधिक थी। 1912 के सहकारी समिति अधिनियम ने एक औपचारिक त्रिस्तरीय संरचना पेश की: गांव स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक और राज्य स्तर पर शीर्ष राज्य बैंक जो अल्पकालिक व मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करते थे। रिजर्व बैंक की सहकारी ऋण आंदोलन में औपचारिक भागीदारी 1951 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की नियुक्ति के साथ गंभीरता से शुरू हुई। समिति ने व्यवस्थागत विफलताओं को स्वीकार किया और एकीकृत ग्रामीण ऋण दृष्टिकोण की वकालत की। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 1919 के मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत सहकारिता राज्य का विषय बन गई थी।

ढांचागत बदलाव मार्च 1966 में आया जब कम से कम एक लाख रुपये की चुकता पूंजी और मुद्रा भंडार वाले सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत लाया गया। इस अधिनियम में संशोधन कर रिजर्व बैंक की नियामकीय अधिकारिता सभी सहकारी बैंकों तक बढ़ा दी गई जिन्हें तब तक केवल राज्य-विशिष्ट सहकारी कानूनों के तहत ही नियंत्रित किया जाता था। इसने दोहरे नियमन की जटिल व्यवस्था कायम की। रिजर्व बैंक जहां बैंकिंग परिचालन और निगरानी करता था वहीं यूसीबी का प्रशासनिक प्रबंधन राज्य सरकारों के पास था।

एस.एस. मराठे समिति (1991) की अनुशंसाओं के बाद रिजर्व बैंक ने यूसीबी के लाइसेंसिंग मानक शिथिल किए ताकि वित्तीय समावेशन बढ़ाया जा सके। 1993 से पहले नए यूसीबी के लिए एक जिला, एक बैंक का सिद्धांत लागू था। 1993 की नीति के बाद यह प्रतिबंध समाप्त हो गया और एक जिले में कई यूसीबी को इजाजत मिली बशर्ते कि उनके लिए बाजार मौजूद हो। अन्य बातों के अलावा नीति ने विशेष लक्षित समूहों द्वारा और उनके लिए प्रोत्साहित किए गए यूसीबी के गठन को बढ़ावा दिया। जैसे महिलाओं के सहकारी बैंक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रोत्साहित बैंक, तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ऋणदाता। इस उदारीकरण ने तीव्र विस्तार को जन्म दिया। मई 1993 से जून 2001 के बीच रिजर्व बैंक ने कम से कम 823 नए लाइसेंस जारी किए और यूसीबी की कुल संख्या 1993 में 1,311 से बढ़कर मार्च 2004 तक लगभग 1,926 हो गई। ये आंकड़े एक अंतर्निहित अस्थिरता को उजागर करते हैं। 2001 में माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का बहुचर्चित पतन इस क्षेत्र की कमजोरियों को उजागर कर गया। परिणामस्वरूप, 2004 में रिजर्व बैंक ने नए यूसीबी लाइसेंस जारी करना पूरी तरह से निलंबित कर दिया और अपना ध्यान विस्तार से हटाकर पुनर्गठन, एकीकरण और बैलेंस शीट की सफाई पर केंद्रित कर दिया। इसके बाद परिसमापन और स्वैच्छिक विलयों के कारण भारत में परिचालन कर रहे यूसीबी की कुल संख्या मार्च 2004 में 1,926 से घटकर मार्च 2025 तक 1,457 रह गई। केवल वित्त वर्ष 25 में ही सात विलय हुए। इस प्रकार वित्त वर्ष 2005 से 2025 के बीच कुल यूसीबी विलयों की संख्या 163 हो गई।

सदी की शुरुआत से वित्त वर्ष 26 तक 488 असफल बैंकों के जमाकर्ताओं ने डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से 18,931.40 करोड़ रुपये का दावा किया। यह रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा करती है। कुल दावों का 98.7 फीसदी असफल सहकारी बैंकों के समाधान में गया जबकि वाणिज्यिक बैंक डीआईसीजीसी के वार्षिक बीमा प्रीमियम राजस्व का लगभग 94 फीसदी योगदान करते हैं। सहकारी बैंक 'एक सदस्य एक वोट' के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित हैं।

हालांकि उन्हें राजनीतिक कब्जे से बचाने के बजाय अक्सर इसका दुरुपयोग किया गया है। प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार को छोड़ दें तो भी राज्य सरकारों ने ऐतिहासिक रूप से राज्य सहकारी अधिनियमों के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग प्रबंधन समितियों को भंग करने, चुनावों में देरी करने और बोर्डों को राजनीतिक नामांकितों से भरने के लिए किया है। फिर भी कुछ सकारात्मक उदाहरण मौजूद हैं। सारस्वत सहकारी बैंक और कॉसमॉस सहकारी बैंक जैसे ऋणदाता दिखाते हैं कि अच्छी तरह से प्रबंधित सहकारी संस्थाएं फल-फूल सकती हैं और जमाकर्ताओं की रक्षा के लिए कमजोर साथियों को भी आत्मसात कर सकती हैं। ऑन-टैप यूसीबी लाइसेंसिंग को फिर से शुरू करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि नियामक को अब भरोसा है कि सांविधिक संचालन सुधारों ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय स्थापित कर दिए हैं। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से किए गए संशोधनों ने सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष और व्यापक निगरानी के अधीन ला दिया जिसमें ऐसे संचालन, अंकेक्षण और प्रबंधन मानक लागू किए गए जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं। वित्त वर्ष 25 में सभी शहरी सहकारी बैंकों की समेकित बैलेंस शीट 4.4 फीसदी बढ़कर 7.39 लाख करोड़ रुपये हो गई जिसमें ऋण 6.7 फीसदी बढ़ा जबकि जमा वृद्धि 5.2 फीसदी रही। आदर्श रूप में यूसीबी भारत की ग्रामीण और कस्बाई आबादी को आखिरी छोर का वित्तीय संपर्क प्रदान करते हैं। अब यह इस क्षेत्र पर निर्भर है कि वह साबित करे कि वह नियामक के विश्वास के योग्य है।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक में वरिष्ठ सलाहकार हैं।)

आपका पक्ष

कृषि भूमि का सिकुड़ना खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती

पिछले तीन-चार दशक से देश में कृषि भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे का विस्तार है। बढ़ती आबादी से आवास और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपजाऊ कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर गैर-कृषि कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। गांव और शहर के समीप के अनेक खेत ,कॉलोनियों में तब्दील हो चुके हैं। यह क्रम लगातार जारी है, लेकिन इस तरह से कृषि भूमि का सिकुड़ना भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है और देश को खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार विकास और कृषि के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है, यही संतुलन आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ी है, लेकिन अनेक कॉलोनियो में निवेशकों द्वारा खरीदे गए अनेक प्लॉट बरसों तक खाली पड़े रहते हैं। इस गंभीर विषय पर सरकार और समाज दोनों को गहनता सोचना होगा। अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण, भूमि उपयोग के नियमों का कठोरता से पालन और सुव्यवस्थित शहरी नियोजन समय की मांग है। ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिनसे खेती में ही स्थिर और सम्मानजनक आय प्राप्त हो, ताकि वे अपनी भूमि कॉलोनाइजरों को बेचने के लिए विवश न हों। यदि हम आज इसके संरक्षण के प्रति सजग नहीं होंगे, तो भविष्य में इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

विमलेश पगारिया, बदनावर

बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण से कम हो रही खेती की जमीन

विदेशी कंपनियां खूब कर रहीं भारत से कमाई

इस समाचार पत्र में प्रकाशित लेख 'विदेशी निवेशकों की राह में दिखते रोड़े' नए सिरे से भारत में विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लाभार्जन को बारीकी से विश्लेषित करने की आवश्यकता पर सोचने को मजबूर करता है। कुछ तथ्य हमारे मानस में बैठ गए हैं कि देश में पूंजी की बहुत कमी है और भारत को वैश्विक व्यापार में स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश बहुत आवश्यक है। अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग देश के कानूनों में अनेक खामियां और आर्थिक प्रशासन तंत्र में विदेशी निवेशकों के प्रति दुराग्रही प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। विदेशी व्यापार, निवेश, आय, कर निर्धारण आदि विषय विश्व के सभी विकसित देशों के समान 'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन' के अनुरूप हैं और एडवांस प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग तथा दोहरे कराधान समझौते वैश्विक कानूनों और समझौतों के अनुरूप हैं, इसलिए भारत में विदेशी निवेशकों, कंपनियों के प्रति किसी दुराग्रही प्रवृत्ति की बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, देश में पूंजी की कमी होने की बात भी गलत है। वास्तविकता यह है कि घरेलू पूंजी जुटाने की कोशिश ही नहीं है। घरेलू बचत को आयकर कानूनों के माध्यम से हतोत्साहित किया गया है और उस पर खत्म हुई है। विदेशी व्यापार में किस सीमा तक ट्रांसफर प्राइसिंग द्वारा लाभ विदेश को स्थानांतरित किया जाता है, इसका मूल्यांकन हो तो सत्य सामने आ जाएगा। विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश और व्यापार भारी लाभ के माध्यम रहे हैं और रहेंगे।

विनोद जौहरी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

चेन्नई के पास महाबलीपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से आग्रह किया कि इस क्षेत्र को आबादी पर नियंत्रण के लिए दंडित न किया जाए और धन हस्तांतरण में उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ, आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के डीके शिवकुमार, केरल के वीडी सतीशन और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भाग लिया।

मुंबई | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 बिज़नेस स्टैंडर्ड

आईटी से लेकर खुदरा क्षेत्र में सुधार से कारोबार दमदार पर पूंजी की दरकार

पृष्ठ 1 का शेष

आईटी विभाग के अधिकारी रविवार को भी कंपनियों के ई-मेल का तेजी से जवाब देते थे ताकि यह संदेश जाए कि पश्चिम बंगाल कारोबार को लेकर काफी गंभीर है। इन कोशिशों पर सबका ध्यान गया।

वर्ष 2004 में 'द इकनॉमिस्ट' पत्रिका ने वामपंथी-शासित कोलकाता में चल रहे सुधारों के दौर पर एक रिपोर्ट छापी थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) और कॉग्निजेंट ने कोलकाता में अपना कारोबार फैलाया, इन्फोसिस ने बाजार परखना शुरू किया और कई आईटी और आईटी समर्थित सेवा कंपनियों ने शहर में अपने दफ्तर खोले।

कोलकाता में टीसीएस का सफर वर्ष 1976 में डलहौजी स्क्वैयर में किराए के एक दफ्तर से शुरू हुआ था। वर्ष 1998 से वर्ष 2008 तक कंपनी के कोलकाता संचालन के प्रमुख रहे अजयेंद्र मुखर्जी कहते हैं, 'बाद में हम साल्ट लेक के सेक्टर 5 में चले गए और वर्ष 2000 की शुरुआत में अपने कामकाज को एक जगह समेटने का निर्णय लिया। हमने 40 एकड़ जमीन के लिए इस शर्त पर आवेदन किया कि उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का दर्जा मिले और प्रस्ताव मंजूर हो गया।'

उन्होंने कहा, 'जिस तेजी से हमारा कारोबार बढ़ रहा था और कोलकाता में जिस कदर प्रतिभाएं मौजूद थीं, साथ ही वहां से काम को जिस गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा था उसे देखते हुए हमें लगा कि हमें यहीं अपने कारोबार का विस्तार करना चाहिए।' टीसीएस कोलकाता में अपनी अलग-अलग जगहों पर 54,000 से अधिक आईटी पेशेवरों को रोजगार देती है। जब कंपनियों ने राज्य के निवेश प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो सरकार ने सॉल्ट लेक से आगे बढ़कर राजारहाट की ओर कदम बढ़ाया जहां पश्चिम बंगाल आवासीय अवसंरचना विकास निगम ने रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक विकास के लिए जमीन के एक बड़े टुकड़े का अधिग्रहण किया था। पश्चिम बंगाल के अगले आईटी केंद्र के लिए मंच तैयार हो चुका था। आज सॉल्ट लेक और न्यू टाउन राजारहाट में कुल मिलाकर लगभग 3,00,000 आईटी पेशेवर काम करते हैं।

बदलाव की बयार

अंबुजा नेवतिया समूह के चेयरमैन हर्षवर्द्धन नेवतिया ने कहा, 'अगर आप शहर के नए हिस्से खासकर न्यू टाउन को देखें तो इसका विकास बहुत शानदार रहा है।'

कोलकाता में टीसीएस की यात्रा डलहौजी स्क्वैयर (ऊपर) में 1976 में एक किराये के कार्यालय में शुरू हुई थी

उन्होंने कहा कि 300 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास वाले इस शहर को आप नए सिरे से दोबारा नहीं बना सकते। निवतिया कहते हैं, 'कोलकाता के कुछ हिस्सों में अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियां हैं मगर यह भी शहर की खासियत का ही एक हिस्सा है।'

सॉल्ट लेक-न्यू टाउन राजारहाट गलियारा केवल एक तकनीकी केंद्र नहीं है। पिछले दो दशकों में यह एक आत्मनिर्भर शहरी ढांचे के तौर पर विकसित हुआ है जहां टेक पार्क और कंपनियों के मुख्यालयों के साथ ही रिहायशी इलाके, व्यावसायिक केंद्र, स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन के केंद्र भी मौजूद हैं।

यह बदलाव शहर के उत्तर-पूर्वी इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा है। कोलकाता के दूसरे हिस्सों में भी एक अलग तरह की चमक आई है।

नेवतिया ने बताया, 'पूरे शहर में खुदरा और मनोरंजन के कई विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण मध्य और उच्च-मध्य वर्ग की खर्च करने लायक आय में बढ़ोतरी है। यह देश और शहर दोनों की आर्थिक तरक्की का स्वाभाविक नतीजा है।'

जैसे-जैसे कोलकाता का विकास हुआ वैसे ही इसके मुख्य केंद्र भी बदलते गए। पार्क स्ट्रीट अब शहर का एकमात्र खानपान का केंद्र नहीं रहा और न्यू मार्केट ने भी खरीदारों के लिए सबसे पसंदीदा जगह होने का अपना रुतबा खो दिया।

पूरे शहर में फैले रेस्तरां, मॉल और मनोरंजन केंद्रों ने कोलकाता में लोगों के रहने, काम करने और आराम करने के तौर-तरीके बदल दिए हैं। साथ ही, मेट्रो तंत्र के विस्तार ने कोलकाता के शहरी विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई और शहर के बाहरी इलाकों तक विकास को रोशनी पहुंचाई है।

वर्ष 1997 में शहर में पहला पैंटालून्स स्टोर खुलने के साथ ही आधुनिक खुदरा कारोबार की शुरुआत हुई। वर्ष 2003 में पहले शॉपिंग मॉल के खुलने से खुदरा क्षेत्र में तेजी आई और जल्द ही प्रीमियम और महंगी जगहों की बाढ़ सी आ गई।

स्पेशियलिटी रेस्टोरेंट्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अंजन चटर्जी उस वक्त को याद कर कहते हैं, 'जब हमने वर्ष 2000 में चीन के साथ कोलकाता में कदम रखा तो शहर में खानपान के क्षेत्र में खास गतिविधि नहीं दिख रही थी। यह बात थोड़ी हैरान करने वाली थी क्योंकि कोलकाता हमेशा से खाने-पीने के शौकीन लोगों की जगह रही है चाहे वह काठी रोल हो, बिरयानी हो या पार्क स्ट्रीट के रेस्तरां हों। मगर इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं था।'

चटर्जी ने कहा कि तब से लेकर अब तक 'कायापलट' हो गई है। उन्होंने कहा कि लोग अब अधिक मुखर हो गए हैं और नए तरह के खानपान के तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कहावत कि 'कलकत्ता के लोग खाने के लिए जीते हैं' पहले से कहीं अधिक सच साबित हो रही है।' मगर कोलकाता आज भी कीमत को लेकर बहुत जागरूक है। चटर्जी कहते हैं, 'हम अपनी डिश की कीमत मुंबई या दिल्ली के बराबर नहीं रख सकते। अमीर वर्ग को छोड़कर मुंबई, दिल्ली, बेंगलूरु, चेन्नई, चंडीगढ़ या पुणे जैसे शहरों की तुलना में यहां लोगों की खर्च करने लायक आय बहुत कम है।'

आय का यह अंतर इस बात का अंदाजा देता है कि कोलकाता अपने समृद्ध अतीत से कितना दूर हो गया है। हालांकि, इसका पतन एक लंबी और उतार-चढ़ाव वाली प्रक्रिया थी जो दशकों तक लगातार मिली चुनौतियों के कारण हुई।

हाथ से निकले मौके

राजनीतिक विश्लेषक सव्यसाची बसु राय चौधरी ने कहा कि कोलकाता का सुनहरा दौर 19वीं सदी के आखिर से 20वीं सदी की शुरुआत तक रहा जब ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के नाते यह एक फल-फूल रहा व्यावसायिक सेंटर बन गया था। फिर इसके फायदे कम होने लगे। बसु राय चौधरी ने बताया, 'दूसरे विश्व युद्ध ने शहर की स्थिति कमजोर कर दी। बंटवारे ने कच्चा जूट जैसे कच्चे माल की आपूर्ति बाधित कर दी और बड़ी संख्या में शरणार्थी आ गए। फ्रेट इक्वलाइजेशन यानी माल ढुलाई खर्च बराबर करने की नीति ने बंगाल की औद्योगिक बढ़त और कम कर दी। वर्ष 1960 और 1970 के दशक तक श्रमिकों की हलचल और मजदूरों के उग्र विरोध प्रदर्शन ने स्थिति और बिगाड़ दी।'

कोलकाता की खोई हुई शान वापस लाना अभी भी एक अधूरा काम है। फिर भी बहुत कम लोग इस बात से इनकार करते हैं कि 'सिटी ऑफ जॉय' भारत के सबसे रहने लायक बड़े शहरों में से एक है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान में अर्थशास्त्र के पूर्व प्राध्यापक अभिरूप सरकार ने कहा कि दूसरे बड़े शहरों की तुलना में कोलकाता रहने के लिए बहुत अच्छा शहर है। सरकार कहते हैं, 'सेक्टर 5 एक आईटी केंद्र बन गया है। यहां कैफे, अस्पताल और सड़कें हैं जो पहले नहीं थीं। बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है और मेट्रो ने आवाजाही आसान बना दी है। ये बदलाव साफ तौर पर दिख रहे हैं।' मगर एक चिंता जगाने वाला रुझान भी नजर आ रहा है। सरकार कहते हैं, 'शहर के कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों की चमक फीकी पड़ गई है। नई पीढ़ी कोलकाता छोड़ रही है। यह पर्याप्त मौकों की कमी का संकेत है और आखिरकार इसका असर इस शहर की खुशहाली पर पड़ता है।'

कई लोगों का कहना है कि कोलकाता की ऊंची इमारतें अब 'वर्टिकल ओल्ड-एज होम' (बुजुर्गों के लिए बहु-मंजिला इमारतें) बन गई हैं। ये शहर में सही मौकों की कमी की याद दिलाती हैं।

टीसीएस के पूर्व वरिष्ठ कार्याधिकारी मुखर्जी के मुताबिक कोलकाता ने कई अहम मौके गंवा दिए। उन्होंने कहा कि शहर में आईटी क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से टीसीएस और दूसरी कंपनियों की वजह से हुई जिन्होंने बाद में इसमें बड़ा योगदान दिया मगर पिछले दो दशकों में हैदराबाद, पुणे और चेन्नई ने कोलकाता को पीछे छोड़ दिया है। मुखर्जी ने कहा, 'कोलकाता के पास इन शहरों से आगे निकलने का हरमौका था।'

पीछे छूटने का यह एहसास केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं है। क्रेडाई पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुशील मोहता ने कहा कि आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार ने शहर के रियल एस्टेट बाजार को सीमित कर दिया है।

मोहता कहते हैं, 'रियल एस्टेट कारोबार का विकास सीधे तौर पर लोगों की क्रय क्षमता से जुड़ा है। रेरा पंजीकृत परियोजनाओं में लगभग 25-30 फीसदी खरीदार एनआरआई या कोलकाता से बाहर रहने वाले लोग हैं। बाजार में पैसा तो खूब आ रहा है मगर यह शहर की आर्थिक तेजी नहीं दिखाता है।'

मोहता का कहना है कि राजारहाट और सॉल्ट लेक जैसे व्यावसायिक इलाके बनने के बावजूद कोलकाता अभी भी बेंगलूरु, पुणे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से पीछे है।

निवेश की लंबी डगर

पश्चिम बंगाल में निवेश का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वर्ष 2000 तक (जब ज्योति बसु ने पद छोड़ा था) कुल निवेश 17,000 करोड़ रुपये था।

जब मई 2011 में भट्टाचार्य ने पद छोड़ा तो पश्चिम बंगाल निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन गया था। उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी और मई 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य के निवेश प्रस्ताव आए थे जो ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी अधिक थे। केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार (वर्ष 2004 से 2008) की अहम सहयोगी पार्टी के तौर पर वाम मोर्चा के रसूख ने भी निवेश प्रस्ताव हासिल करने में मदद की।

ममता बनर्जी सरकार के पिछले पांच वर्षों यानी 2021 से दिसंबर 2025 तक पश्चिम बंगाल को कुल 60,058 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। डीपीआईआईटी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में 39,306 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ पश्चिम बंगाल देश में पांचवें स्थान पर रहा। निवेश के आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। जैसा हर्षवर्द्धन नेवतिया ने कहा, 'हर शहर एक इंसान की तरह होता है। उसकी अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। कोलकाता एक मिलनसार, मानवीय और रहने लायक शहर के तौर पर विकसित हुआ है।'

कुछ मायनों में यह शहर के अतीत की याद दिलाता है। बसु राय चौधरी ने कहा, 'कोलकाता कभी बहुत विविध संस्कृतियों वाला शहर था जिस पर यूरोप की भी छाप दिखती थी। चौरंगी, पार्क स्ट्रीट और फ्री स्कूल स्ट्रीट औपनिवेशिक गलियारे का हिस्सा थे, और अंग्रेज अधिकारियों के चले जाने के काफी समय बाद भी शहर की वास्तुकला, खानपान और जीवन-शैली पर उनकी छाप बनी रही। साथ ही, ओडिशा और बिहार से आए प्रवासियों ने शहर को एक नई पहचान दे दी।' अपनी आर्थिक बढ़त खोने के बावजूद कोलकाता ने 'जियो और जीने दो' की भावना बरकरार रखी है।

शेयर बाजार

खबरों में

बलरामपुर चीनी मिल्स

Top gainer amongst A-group of companies

₹ 650.9 PREVIOUS CLOSE
₹ 766.6 CLOSE
▲ 17.8% UP

नेटवेब टेक्नॉलजीज इंडिया

Hits new all time high on BSE at ₹5,449

₹ 5,062.2 PREVIOUS CLOSE
₹ 5,418.9 CLOSE
▲ 7.0% UP

अंबुजा सीमेंट

Snap 10-day losing streak

₹ 406.0 PREVIOUS CLOSE
₹ 411.0 CLOSE
▲ 1.2% UP

*OVER PREVIOUS CLOSE

आज का अहम शेयर

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस

Hits new high at ₹₹658, Surged 45 per cent YTD

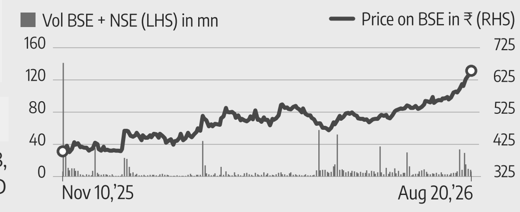

निफ्टी 50

Company	Close (₹) 20 Aug '26	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std	Company	Close (₹) 20 Aug '26	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std
Adani Enter	2994.9	0.2	0.9	157.5	121.8	JSW Steel	1299.7	1.1	1.5	32.5	42.2
Adani Ports	1696.0	0.8	1.1	29.4	141.5	Kotak Mah Bank	397.4	1.8	2.5	19.7	26.6
Apollo Hosp	8735.0	-0.2	0.8	59.7	79.5	L & T	4081.0	1.0	4.8	31.5	41.8
Asian Paints	2625.2	-0.2	1.0	51.6	53.1	Mah & Mah	3424.8	0.3	3.0	22.1	26.1
Axis Bank	1251.0	1.3	3.1	14.0	15.1	Maruti Suzuki	13809.0	0.9	1.5	30.3	30.9
Bajaj Auto	11793.0	1.3	1.3	27.5	30.2	Max Health	997.9	0.1	0.6	64.9	132.9
Bajaj Fin	1095.0	1.4	2.7	33.3	37.5	Nestle India	1458.0	-0.5	0.9	75.9	74.9
Bajaj Finsrv	2016.0	0.2	1.1	31.0	145.6	NTPC	337.5	0.3	1.4	11.8	13.8
Bharat Elctn	409.4	0.0	1.3	48.7	48.9	ONGC	238.5	0.2	1.1	6.9	7.2
Bharti Airtel	1941.7	1.0	5.2	38.1	70.3	Power Grid	264.8	0.5	1.0	15.5	15.7
Cipla	1438.0	1.1	0.7	32.5	35.4	Reliance Ind	1313.2	0.2	7.7	23.8	45.3
Coal India	402.5	0.6	0.8	7.9	13.1	SBI	1048.0	-0.1	3.7	11.5	12.3
Dr Reddys	1180.0	0.9	0.6	30.6	148.4	SBI Life Ins	1782.0	0.1	0.7	-	68.8
Eicher Motor	8042.0	0.6	1.0	38.0	41.8	Shriram Finance	1128.2	2.0	1.8	23.5	23.5
Eternal	328.0	2.5	2.7	728.8	120.1	Sun Pharma	1904.0	0.2	1.8	36.2	143.5
Grasim Ind	3300.0	0.9	1.1	38.4	266.6	Tata Consumer P	1056.3	-1.1	0.6	63.4	63.4
HCL Techno	1318.4	-0.5	1.2	19.7	19.7	Tata Motors PV	320.3	-0.3	0.6	129.1	187.3
HDFC Bank	725.1	0.7	9.6	14.1	14.8	Tata Steel	183.5	-0.3	1.3	19.3	12.8
HDFC Std Life	542.0	1.1	0.5	59.6	59.6	TCS	2298.0	0.4	2.0	15.5	15.4
Hindalco	1029.9	-0.9	1.3	11.1	17.8	Tech Mahindra	1592.1	0.1	0.9	29.3	39.1
HUL	2028.0	0.4	1.6	43.2	44.1	Titan Company	5068.0	0.0	1.8	77.1	83.9
ICICI Bank	1411.9	0.7	8.7	18.1	19.4	Trent	2970.0	0.6	0.9	86.6	75.5
Infosys	1130.0	0.9	3.4	14.7	14.7	UltraTech	11575.0	1.1	1.2	39.5	44.6
InterGlobe Avia	5165.0	-0.5	1.0	-	-	Wipro	181.0	0.8	0.4	13.6	15.9
ITC	271.7	1.7	2.9	17.2	17.8	Wipro					
Jio Financial	244.6	0.6	0.7	78.1	226.5	**Nifty 50**	**24231.9**	**↑0.6**	**100.0**	**22.1**	**26.4**

एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स स्टॉक

Company	Close (₹)	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std	Company	Close (₹)	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std
Adani Ports	1693.3	0.8	1.4	29.4	141.2	L & T	4072.0	1.0	5.9	31.4	41.7
Asian Paints	2625.0	0.2	1.2	51.6	53.1	Mah & Mah	3440.7	0.8	3.7	22.2	26.2
Axis Bank	1250.4	1.5	3.7	14.0	15.1	Maruti Suzuki	13788.6	0.7	1.9	30.2	30.9
Bajaj Fin	1095.2	1.5	3.2	33.3	37.5	NTPC	338.0	1.0	1.7	11.8	13.8
Bajaj Finsrv	2016.5	0.3	1.4	31.0	145.6	Power Grid	265.3	1.1	1.3	15.5	15.7
Bharat Elctn	408.7	0.0	1.5	48.6	48.8	Reliance Ind	1315.6	0.6	9.4	23.8	45.4
Bharti Airtel	1943.5	1.0	6.3	38.1	70.4	SBI	1047.4	0.1	4.5	11.5	12.3
Eternal	327.6	2.3	3.3	728.0	120.0	Sun Pharma	1901.0	0.2	2.2	36.1	143.3
HCL Techno	1320.0	-0.2	1.5	19.8	19.7	Tata Steel	183.3	-0.4	1.6	19.3	12.7
HDFC Bank	726.5	0.9	11.7	14.2	14.8	TCS	2292.6	0.2	2.4	15.4	15.4
HUL	2036.7	1.0	1.9	43.4	44.3	Tech Mahindra	1592.0	0.6	1.1	29.3	39.1
ICICI Bank	1411.5	0.7	10.6	18.1	19.4	Titan Company	5062.0	0.0	2.2	77.0	83.8
Infosys	1130.2	1.2	4.2	14.7	14.7	Trent	2968.0	0.8	1.0	86.6	75.5
InterGlobe Avia	5162.6	-0.2	1.2	-	-	UltraTech	11595.0	1.2	1.5	39.6	44.7
ITC	271.3	1.6	3.5	17.2	17.8	**BSE SENSEX**	**77537.7**	**↑0.8**	**100.0**	**21.9**	**25.8**
Kotak Mah Bank	398.5	1.6	3.1	19.8	26.7						

C = Consolidated; S = Standalone

वैश्विक सूचकांक

Indices	Close	% Chg*	Indices	Close	% Chg*
Americas (Aug 19,26)			**Asia/Pacific (Aug 20,26)**		
Dow Jones	53463.1	0.2	Kospi	6852.6	5.9
Nasdaq Composite	26331.1	0.2	Jakarta Composite	6501.6	1.7
S&P/ TSX Composite	36401.8	0.1	Taiwan Taiex	44933.7	0.5
Europe/Africa (Aug 19,26)			Kuala Lumpur Comp	1736.7	0.3
IBEX 35	19889.3	0.2	Shanghai Se Comp	3903.7	0.2
FTSE 100	10725.5	-0.2	Stock Exchange of Thai (Aug 19)	1610.0	0.0
CAC 40	8485.6	-0.2	Straits Times	5671.9	-0.4
DAX	25987.6	-0.4	**Volatility (Aug 19,26)**		
Asia/Pacific (Aug 20,26)			CBOE S&P 500	15.2	2.0
Nikkei 225	66216.8	1.4	CBOE Dow Jones	13.1	-3.5
Hang Seng	25698.5	0.8			

* Change over previous close

प्रमुख सूचकांक

	Previous Close	Open	High	Low	Close	Change	% chng
BSE Sensex	76,909.7	77,468.5	77,611.1	77,371.0	77,537.7	628.0	0.8
BSE Sensex 50	25,276.1	25,457.2	25,487.9	25,411.2	25,461.2	185.2	0.7
BSE-100	25,829.8	26,006.1	26,042.4	25,959.6	26,003.8	174.0	0.7
BSE-200	11,336.3	11,414.0	11,427.6	11,393.6	11,407.3	71.0	0.6
BSE-500	36,577.2	36,822.8	36,882.7	36,774.8	36,808.4	231.3	0.6
BSE IPO	18,238.1	18,340.3	18,406.4	18,328.1	18,359.4	121.3	0.7
Dollex-30	6,593.9	-	-	-	6,651.5	57.6	0.9
Nifty 50	24,078.3	24,225.5	24,265.2	24,184.6	24,231.9	153.5	0.6
Nifty Next50	73,900.7	74,229.4	74,359.3	74,055.3	74,194.2	293.5	0.4
Nifty 500	23,386.2	23,519.8	23,565.9	23,491.6	23,513.0	126.8	0.5
India VIX	11.3	11.3	11.3	9.3	10.8	-0.6	-5.0
Nifty CPSE	6,405.2	6,424.5	6,442.4	6,371.2	6,429.1	23.9	0.4

बढ़े/घटे

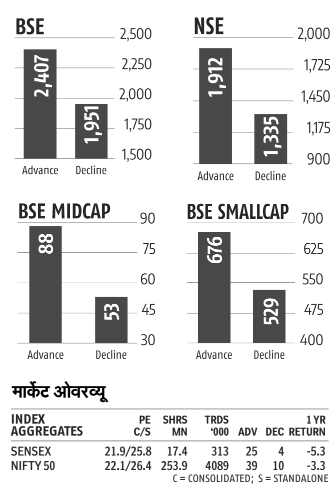

मार्केट ओवरव्यू

INDEX AGGREGATES	PE C/S	SHRS MN	TRDS '000	ADV	DEC	1 YR RETURN
SENSEX	21.9/25.8	17.4	313	25	4	-5.3
NIFTY 50	22.1/26.4	253.9	4089	39	10	-3.3

C = CONSOLIDATED; S = STANDALONE

TURNOVER	CASH BSE	CASH NSE	DERIVATIVES BSE	DERIVATIVES NSE
VALUE(IN ₹ CRORE)	9340	108314	48497753	8640675
SHARES(IN MN)	589.3	4423.1	692	20128.6
TRADES(000)	3329	34825	-	28473

MARKET-CAP (₹ CR)	TRADED	TOTAL
BSE	49,127,448	49,427,093
NSE	48,936,609	49,189,424
DERIVATIVES	34,361,289	34,361,289

कारोबारी गतिविधि

(₹ crore)	FIIs Equity Net	FIIs Debt Net	MF Equity Net	MF Debt Net
On 19 Aug	495	135	-	-
On 18 Aug	2926	-199	-	-
On 17 Aug	-339	95	-	-
On 14 Aug	4112	-728	-	-
On 13 Aug	351	-1523	4572	5954
Aug till date	22464	-143	30357	-35384
2026 till date	-225761	63455	344466	-566847

डेरिवेटिव में एफआईआई

(₹crore)	Index NET	Stock Net	Index Fut OI	Index Opt OI	Stock OI
On 19 Aug	-21619	-650	0.3	2.9	7.8
On 18 Aug	-26192	-2894	0.2	2.4	7.8
On 17 Aug	7637	-282	0.2	3.0	7.7
On 14 Aug	4273	-706	0.2	2.8	7.7
On 13 Aug	-14108	-42	0.2	2.6	7.6
Aug till date	-66257	-8994	-	-	-
2026 till date	-748218	-81191	-	-	-

OI in number of contracts(million)

एसएंडपी बीएसई सेक्टर सूचकांक

	Prev cls	Close	% Chng
Auto	64,440.5	64,701.6	0.4
Bankex	64,793.5	65,110.6	0.5
Cons. Durables	64,854.3	65,092.8	0.4
Cap. Goods	79,087.3	79,168.6	0.1
FMCG	17,917.5	18,102.8	1.0
Healthcare	50,591.5	50,713.5	0.2
Infra	571.2	573.0	0.3
IT	29,184.2	29,457.2	0.9
Metal	41,597.5	41,698.1	0.2
Oil & Gas	26,122.4	26,143.2	0.1
Power	7,471.7	7,493.7	0.3
PSU	20,656.5	20,679.4	0.1
Realty	6,964.4	7,094.6	1.9

एफएंडओ स्नैपशॉट

MOST BULLISH	Futures price	Cash price	Premium (%)	MOST BEARISH	Futures price	Cash price	Discount (%)
GE T&D Ind	4080.9	4050.1	0.8	LIC Hsg Fin	498.5	508.1	-1.9
Tata Consumer P	1063.6	1056.3	0.7	JSW Steel	1287.2	1299.7	-1.0
HCL Techno	1327.4	1318.4	0.7	Ruchi Soya	349.0	352.3	-0.9
Bandhan Bank	175.3	174.2	0.6	HDFC AMC	2601.0	2624.0	-0.9
Rail Vikas Niga	229.3	227.9	0.6	LTIMindtree	4514.2	4553.0	-0.9

	BSE Index	BSE Stock	NSE Index	NSE Stock
FUTURE				
Contracts	1362	8	138452	4447711
Open Int.(000)	3	0	22282	19708025
Shares(In Mn)	0	0	8.4	7462.6
Value(₹ crore)	212	0	22489	301308
OPTIONS				
Contracts	312891747	18	47928161	9447233
Open Int.(000)	6354	0	571266	10262274
Shares(In Mn)	69	0	2977.8	9679.8
Value(₹ crore)	48497540	1	7636599	680280

पुट कॉल रेशियो

(Open Interest in Mn)	Put	Call	PC Ratio
Market	4180.9	6652.7	0.6

Top 5	PC Ratio	Bottom 5	PC Ratio
Bajaj Auto	1.2	Page Inds	0.3
MCX	1.0	GAIL	0.4
Samvardhana M	1.0	Godfrey Ph	0.4
NIIT Techno	1.0	Tech Mahindra	0.4
PNB	1.0	Shree Cement	0.4

एक्टिव कॉल

(In Million)	Expiry Date	Strike Price	Traded Qty	Open Interest	% Chg (OI)
Index					
Nifty	25/08/26	24200	150.2	8.4	-24.4
Nifty	25/08/26	24300	124.0	9.9	-15.2
Nifty	25/08/26	24250	105.8	4.2	11.7
Nifty	25/08/26	24500	87.1	12.6	-16.1
Nifty	25/08/26	24400	75.3	8.3	-5.5
Stock					
Vodafone Idea	25/08/26	15	431.4	354.2	-0.3
Vodafone Idea	25/08/26	14	385.2	251.2	-21.4
YES Bank	25/08/26	23	76.1	65.7	-18.7
Vodafone Idea	29/09/26	14	75.3	170.3	20.8
Vodafone Idea	29/09/26	15	67.0	171.1	12.9

एक्टिव पुट

(In Million)	Expiry Date	Strike Price	Traded Qty	Open Interest	% Chg (OI)
Index					
Nifty	25/08/26	24200	197.0	13.7	110.0
Nifty	25/08/26	24250	106.2	5.0	359.9
Nifty	25/08/26	24300	94.1	7.5	54.8
Nifty	25/08/26	24000	74.4	16.5	18.1
Nifty	25/08/26	24100	62.1	7.7	12.4
Stock					
Vodafone Idea	25/08/26	14	214.2	193.1	-12.7
Vodafone Idea	25/08/26	13	87.5	212.3	-5.1
Vodafone Idea	29/09/26	14	34.5	77.3	25.3
YES Bank	25/08/26	23	30.2	56.3	-11.4
Vodafone Idea	29/09/26	13	26.0	60.8	14.8

वॉल्यूम में तेजी

Company	Days Volume	2-week Avg Volume	Change %	Close price	*Price %chg
ZF Steering	125182.0	347.9	35881.2	669.0	-2.2
GSM Foils	4245500.0	27818.2	15161.6	87.9	4.8
Mangalam Cem	2778430.0	34245.8	8013.2	982.7	9.5
Solara Active P	7174916.0	171698.8	4078.8	638.1	16.0
Balram Chini	35741816.0	874471.7	3987.2	766.5	17.8
MMTC	44431348.0	1368011.7	3147.9	66.3	6.8
Somi Conv	747915.0	26618.0	2709.8	100.3	15.4
Bharat Global D	200432.0	8867.8	2160.2	103.2	20.0
Kronox Lab Sci	6528715.0	294290.5	2118.5	186.4	20.0
Strides Pharma	5345887.0	251117.6	2028.8	992.0	3.7

52 सप्ताहों का उच्चतम और निम्नतम

Company	Price	Company	Price	Company	Price	Company	Price
HIGH		*Liquidbetf	1095.4	**LOW**		Ace Engitech	95.0
BS 200		*ICP AMC Cs	1076.0	BS 200		*Prithvi Exch	91.0
*Netweb Technolo	5448.8	*Mirae -ET	1000.0	*ITC	265.1	*Emiac Tech	87.1
*PNB Hou Fin	1207.0	*Kalyani Cast-Te	989.0	Others		*AB Life Brand	86.2
*Sona BLW Precis	843.9	*Zelio E Mobili	848.7	*Proct & Gamb	8230.0	*Sai Silks	84.6
*RBL Bank	393.8	*Shilpa Medi	835.2	Astrazen Ph	7480.2	*Xelpmoc Des	75.1
Others		Avadh Sugar	826.5	*Aurionpro Sl	680.8	*Adcounty Media	73.0
Victoria Mls	7373.5	*SG Mart	824.1	*Brady & Morr	672.0	*Himatsing S	68.5
*TVS Srichakr	5027.5	*Pricol	822.4	Medplus Health	647.3	Indo Thai Secur	62.8
Bannr Am Sug	4345.0	*Khazanchi Jewel	809.5	Bikaji Foods	585.6	Vega Jeweller	62.0
*Sedemac Mech	3350.0	*Balram Chini	781.0	*Sun TV Net	474.2	VTM	45.0
*R R Kabel	2924.9	*Exato Tech	740.7	Ind.Link Chain	456.6	Paos Inds	40.2
*Avalon Technol	2350.0	*Rishabh	729.3	Vesuvius	428.8	*Supreme Ho	38.0
*Happy Forgings	2338.8	*Man Ind	699.0	*KEC Intl	422.1	*Caprola.Chem	37.1
*Welspun Corp	2016.8	Coral Lab	679.0	*Shanthi Gear	385.7	*Quality RO Ind	36.0
Bosch Home	1799.3	*Axisol	667.8	*Nitin Castings	278.2	*Prospect Comm	32.0
*SEAMEC	1721.1	Raymond	659.0	*City Puls Mult	207.4	*Syschem (I)	29.3
*Ador We	1692.0	*Lenskart	657.5	*Suraj Ltd	191.7	*Fiberweb I	25.9
*RPEL	1665.9	Dolphin Off.	654.1	Star Cement	191.5	*Stanbik	24.8
*Sai Life Scienc	1482.0	Elgi Equip	641.6	*Crizac Ltd	169.0	Davin	22.9
*Inv & Prec	1369.2	Magadh Sugar	630.0	*Greenpanel Inds	158.2	11Amd	22.1
*Nippon Life Ind	1266.3	Apollo Pipes	604.9	SAFE	135.0	*Aayush Food	21.7
Sundram Fast	1255.0	*Bliss GVS	601.3	Kitex Garmnt	123.3	*Bandaram	17.3
*Sudeep Pharma	1189.4	*Dhabriya Poly	595.0	*National Std	122.1	*Takyon	17.0
*Maha Steel	1160.0	*Jattashankar in	590.0	*Rex Sealing	111.0	*Howard Htl	16.7
*Liquidadd	1141.1	*Schloss	544.7	*SKCIL	96.7	*Essar Ship	15.8
*Liquid ETF	1118.0	Kabra Extrus	540.5	Crescentis Cap	95.4	Burnpur Cem	14.9

* Indicates that the market price of these companies reached two-year highs/lows.

दिन में सबसे ज्यादा चढ़े

Company	Day's high	Close	% chg*	3mth high	52 wk high
Netweb Technolo	5448.8	5418.9	7.0	5448.8	5448.8
MCX	3132.0	3121.0	5.0	3479.8	3479.8
Muthoot Finance	2997.3	2972.0	3.9	3390.0	4149.0
Coforge	1888.7	1880.0	3.6	1888.7	1988.9
Motilal Oswl	989.2	971.1	3.5	989.2	1097.0
Hind Zinc	574.4	573.0	3.4	659.8	732.6
Billionbrains	201.6	200.7	3.3	221.0	227.0
Piramal Pharma	216.9	216.5	3.3	218.4	218.4
SBI Card & Pay	654.6	646.1	3.2	674.1	965.0
Macrotech Devlp	1246.0	1244.0	3.2	1344.0	1344.0
RBL Bank	393.8	392.9	3.1	393.8	393.8
Glenmark	2341.6	2325.0	3.1	2422.4	2471.1
Persistent S	5703.4	5680.0	3.1	5703.4	6597.0
Premier Energie	1050.0	1037.3	2.9	1134.0	1134.0
HDFC AMC	2610.0	2610.0	2.8	2837.7	2965.0

दिन में सबसे ज्यादा गिरे

Company	Day's low	Close	% chg*	3mth low	52 wk low
Himadri Sp Chem	695.1	703.7	-6.2	578.0	420.0
Power Fin	363.3	364.0	-3.2	363.3	330.1
Bharat Dyn	1308.2	1311.3	-2.8	1156.0	1090.0
REC	327.7	328.8	-2.5	321.1	304.1
Sammaan Capita	149.6	150.3	-2.2	144.9	116.8
GMR Airports	100.1	100.1	-2.1	94.7	84.0
Indraprst Gs	150.2	150.5	-1.7	147.3	141.6
HFCL	222.7	223.6	-1.3	138.9	59.8
HUDCO	184.6	186.2	-1.3	184.6	159.0
BHEL	412.3	414.0	-1.1	367.9	205.2
Federal Bank	355.8	355.8	-1.0	283.1	188.5
Uno Minda	1262.3	1262.3	-1.0	1032.0	994.0
Nestle India	1455.0	1456.7	-0.9	1368.8	1145.1
Apollo Hosp	8680.0	8720.0	-0.9	7874.3	6680.0
IndusInd Bank	1002.8	1003.1	-0.9	874.1	710.9

* Ranked on the basis of percentage gain/loss on previous close

सबसे ज्यादा कारोबार

	Value BSE+NSE (₹ crore)	Volume BSE+NSE (Mn shrs)
Balram Chini	2634.9	35.7
Netweb Technolo	2558.1	4.8
Dhoot Transmiss	2256.0	15.6
Shiprocket	1819.9	121.2
BSE	1804.1	5.4
HDFC Bank	1504.5	20.7
Behari Lal Eng	1391.2	26.2
MCX	1323.5	4.3
ICICI Bank	1300.5	9.2
Eternal	1261.8	38.6
Milky Mist	1184.7	60.3
Billionbrains	1091.2	55.1
Dixon Tech	1050.4	0.7
Infosys	1004.4	8.9
Himadri Sp Chem	959.6	13.3
LIC India	905.6	21.6
Bharti Airtel	888.7	4.6
Aster DM Health	860.5	11.1
Coforge	828.5	4.4
Nippon Silver	826.9	36.6
PAYTM	811.1	5.0
Reliance Ind	792.3	6.0
Bajaj Fin	781.4	7.1
ITC	780.9	29.1
Cupid Ltd	771.6	27.3

प्रमुख एम-कैप

Rank	Company	Mcap (₹ cr)
1	Reliance Ind	1780273.3
2	Bharti Airtel	1212841.2
3	HDFC Bank	1119616.4
4	ICICI Bank	1012948.9
5	SBI	966766.9
6	TCS	829467.5
7	Bajaj Fin	681840.4
8	L & T	560246.1
9	LIC India	532565.0
10	HUL	478531.3
11↑	Infosys	458641.9
12↓	Sun Pharma	456106.9
13	Titan Company	449404.4
14	Maruti Suzuki	433513.6
15	Mah & Mah	427851.7
16	Adani Enter	404808.7
17↑	Kotak Mah Bank	396403.9
18↓	Adani Power	392443.6
19	Adani Ports	390116.3
20	Axis Bank	389208.9
21	HCL Techno	358188.2
22	UltraTech	341680.0
23↑	ITC	339870.8
24↓	HAL	334055.6
25	NTPC	327747.4
26	Bajaj Finsrv	323063.5
27	Bajaj Auto	322917.5
28	JSW Steel	316936.8
29	Eternal	316147.1
30	ONGC	299536.5

रुझान

Company	% change	Company	% change
BS200		**DOWN 7 DAYS**	
UP 7 DAYS		Mardia Samyoung	-30.1
Supreme Ind	6.7	Onix Solar	-30.1
UP 3 DAYS		Ujaas Ener	-30.1
Dixon Tech	5.7	City Puls Mult	-30.1
Kaynes T	4.9	RSD Fin	-30.1
HDFC AMC	3.5	Indo Thai Secur	-30.0
Petronet LNG	3.0	CCME Global	-30.0
APL Apolo Tb	3.0	**UP 3 DAYS**	
Grasim Ind	1.0	Mysore Petro	52.2
DOWN		TPI India	34.1
Himadri Sp Chem	-10.7	11Qpr	32.9
BHEL	-4.8	Osiajee Texfab	32.4
Cummins (I)	-4.5	08Agg	31.4
Force Motors	-4.1	Baj Hind Sug	31.0
Voltas	-3.7	Prabha Energy	30.4
KEI Ind	-3.5	**DOWN 3 DAYS**	
CAMS	-3.4	Utcrfs2Dgr	-27.1
Others		Citizen Solar	-14.2
UP 7 DAYS		ANG Lifescience	-14.2
Victoria Mls	45.6	Covance	-14.2
Darjeeling Rope	40.7	ABans Enterpris	-14.2
Taaza Int	40.7	Centuple Global	-14.1
LE Lavoir	40.6	Prima Innovatio	-14.0
Maxgrow	40.6		
Kuber Udyog	40.6		
Steelco Guj.	40.5		

बोर्ड बैठक

Group Company Purpose

AUGUST 21

Aarshyam: To consider inter-alia the proposal of fund raising

Amalgamated Ele: To consider and approve the convening of the 91st Annual General Meeting and to approve the draft Notice thereof, including the date, time, venue/mode and other related matters

Ashiana Agro: To consider and approve the convening of Annual General Meeting on 25th September, 2026 at 11 AM through VC/OAVM and to approve Secretarial Audit Report for 2025-26.

Continental Che: Meeting of the Board of Directors of the Company

Dee Development: Meeting of the Board of Directors of the Company

Emkay Global: To consider and approve the Issuance of unsecured Non-Convertible Debentures on private placement basis.

Federal Bank: To consider and approve the proposal for raising funds

Flexituff Vent: To consider and approve Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2026.

Global Infratec: To consider and approve agenda related to AGM

ICICI Bank: To consider and approve the revision of fund raising limit by way of issuance of bonds/notes/offshore certificate of deposits in overseas markets.

Indobell: To consider and approve Fixing the AGM Date Increase in Authorised Capital Approval of Directors Report

Innova Captab: To consider approve and take on record the revision of standalone and consolidated financial statements

Interise: Borrowing by way of term loan or issuance of securities instruments

J J Finance: To consider and approve Notice of Board Meeting for fixing the date of AGM and book closure.

KACL: Scheme of Arrangement & A.G.M.

Lesha Inds: To consider and approve:- 1. Appointment of Statutory Auditor of the Company 2. Any other matter with consent of chair.

Ncl Research: To consider and approve agenda related to fund raising via Right Issue

New Swan Multit: To consider and approve The declaration of Interim Dividend on the Equity Shares of Face Value of ₹10/- each of the Company for the Financial Year 2026-2027.

Octavius Plant: Audited Results & A.G.M.

Step Two Cor: To consider and approve 1. Venue Date and Time for conducting Annual General Meeting for FY 2025-2026. 2. To approve the Annual General Meeting Notice for FY 2025-2026. 3. Any other business with the permission of the Chair.

Sunrise EM: To consider and approve the date time venue and other arrangements for convening the 06th Annual General Meeting of the Company.

इंट्रा-डे

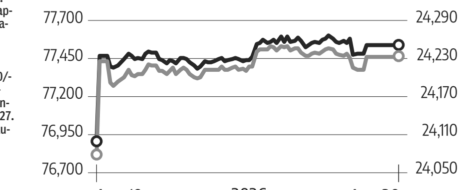

ANNUAL GENERAL MEETING

AUGUST 21
Group A
Lloyds Engineer
KEC Intl
VIP Ind
Tourism Fin
SML Mahindra
ICICI Bank
Minda Corporati
CSB Bank
Federal Bank
Grasim Ind
Group B
Mangalam Cem
Kanco Tea
Polyspin Exp
LG Electronics
BCPL Railway
Neogen Chem
Group M
Bondada
Group MT
Jonjua Overseas
Astonea Labs
Group T
Alkali Met
Group X
Sayaji Indore
Guj Terc Lab
Oxygentaph
Group XT
Shentracon C
Geetanjali Cred
Prabhhans Inds
Quantum Digt
Shakti Press
Jasch Ind
Group Z
Gangotri Tex
AUGUST 22
Group B
Steel Exchng
Crest Ventures
Group M
Angel Fibers
Group T
Kotyark Inds
Group X
Lords Ish
G.K.Consult
AUGUST 24
Group A
Coforge
Bandhan Bank
HUDCO
Astral
Lumax Tech
Chennai Petr
MRPL
Godfrey Ph
Group B
Lumax Ind
Munjal Showa
Suryalta Spg
Wework
Fabtech Techno
BMW Ventures
Mah.Ras.Apex
Money Master
KSR Footwear

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

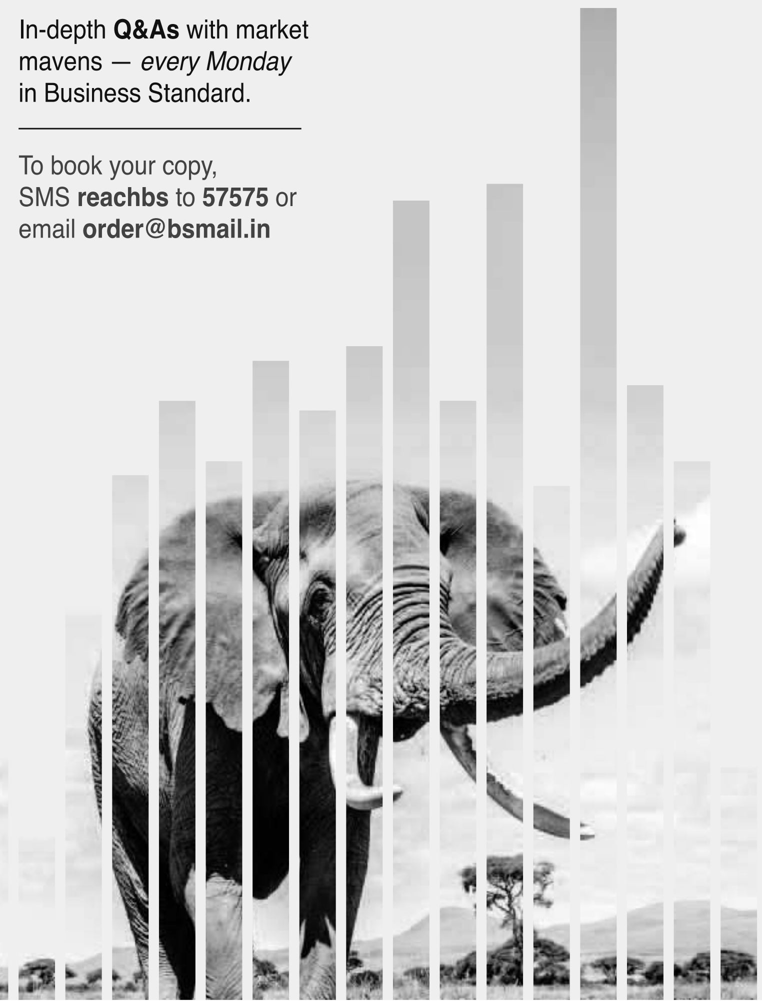

Business Standard
Insight Out

businessstandard bsindia business.standard business-standard.com

सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड

(पूर्व में चैम्पियन सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड)

CIN No.: L26942OR1991PLC002865

पंजीकृत कार्यालय एवं वर्कशॉपः ग्रामः बरपाली, डाकघरः केसरामल, राजगंगपुर, जिलाः सुंदरगढ़, ओड़िशा, भारत, पिनः 770017

दूरभाषः +91-9437049074, ई-मेलः info@surajproducts.com, companysecretary@surajproducts.com, वेबसाइटः www.surajproducts.com

सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों को 35वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

1. सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ग्राम बरपाली, डाकघर-केसरामाल, राजगांगपुर, जिला-सुंदरगढ़, ओडिशा-770017 में आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम बुलाने संबंधी नोटिस में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अनुशंसापत्रों का उपयोग करके शेयरधारक/सदस्य लॉगिन के अंतर्गत https://www.evoting.nsdl.com पर कथित सूचना को देख सकते हैं।
2. प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम की सूचना तथा वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेज कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गण) के पास पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://surajproducts.com/annual-reports, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एवं ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।
3. इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुपालन में, उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं। इस पत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध होने वाले वेब-लिंक सहित उसका सटीक पथ प्रदान किया गया है।
4. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 को लागू नियमों के साथ पढ़े जाने के अनसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तिकाएँ शनिवार, 5 सितंबर, 2026 से शनिवार, 12 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। यदि प्रस्तावित लाभांश को एजीएम में अनुमोदित किया जाता है, तो ऐसे लाभांश का भुगतान कंपनी के उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 05 सितंबर, 2026 (रिकॉर्ड तिथि) को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
5. केवाईसी पंजीकरण/ई-मेल पते को अद्यतन करने की प्रक्रियाः
   (क) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए गए हैं, तो केवाईसी विवरण एवं नामांकन के पंजीकरण/परिवर्तन हेतु संबंधित प्रपत्र, अर्थात प्रपत्र आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14 तथा सेबी के परिपत्र हमारी वेबसाइट https://surajproducts.com पर उपलब्ध हैं। फोलियो को केवाईसी अनुपालनयुक्त बनाने के लिए धारक को उसमें उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए प्रपत्र जमा करना आवश्यक है।
   (ख) डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते जिस डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास रखते हैं, उसके साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएँ।
6. ई-वोटिंग के माध्यम से मत/मतों के प्रयोग करने का तरीकाः
   क) सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यसूची के विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना मत/मतों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।
   ख) डिमैटेरियलाइज्ड रूप में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा रिमोट तरीके से (रिमोट ई-वोटिंग) मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइट https://surajproducts.com/annual-reports पर भी उपलब्ध होगा।
   ग) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत/मतों का प्रयोग नहीं किया है, एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे।
   घ) ई-वोटिंग के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने हेतु लॉगिन अनुशंसापत्र सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है अथवा जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के टिप्पणियों में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन अनुशंसापत्र प्राप्त कर सकते हैं।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान मतदान करने की प्रक्रिया का अवलोकन करें।
8. सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **बुधवार, 09 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भामास) से शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को सायं 5:00 बजे (भामास) तक (दोनों दिन सम्मिलित)** रहेगी।
9. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **शनिवार, 05 सितंबर, 2026** को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में) डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी होगा।

कृते सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
अनंत नारायण खटुआ
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं.: ए21776

स्थान : बरपाली
दिनांक : 19 अगस्त, 2026

IDBI BANK
CIN:L65190MH2004GOI148838

एनपीए प्रबंधन समूह, आईडीबीआई टावर, 11वीं मंजिल, विंग, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005.
सीआईएन सं.: L65190MH2004GOI148838

मास्टर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास विधिवत पंजीकृत साधारण बीमा कंपनियों/फर्मों से, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड तथा अन्य ऋणदाताओं के पक्ष में प्रभारित बंद अथवा गैर-परिचालित इकाइयों की परिसंपत्तियों के बीमा हेतु मास्टर इंश्योरेंस पॉलिसी (एमआईपी) के अंतर्गत मानक बीमित जोखिमों सहित सेंधमारी एवं अग्नि जैसे अनचाहे जोखिमों के कवरेज के लिए प्रीमियम दरों के कोटेशन प्राप्त करने के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 03 सितंबर 2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक है. अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वेबसाइट **www.idbibank.in** के तहत नोटिस एवं निविदाएं देखें. उक्त के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा तथा अलग से कोई भी सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी.

दिनांक : 21/08/2026 **ह./-(मप्र- एनएमजी)**

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — *every day* with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

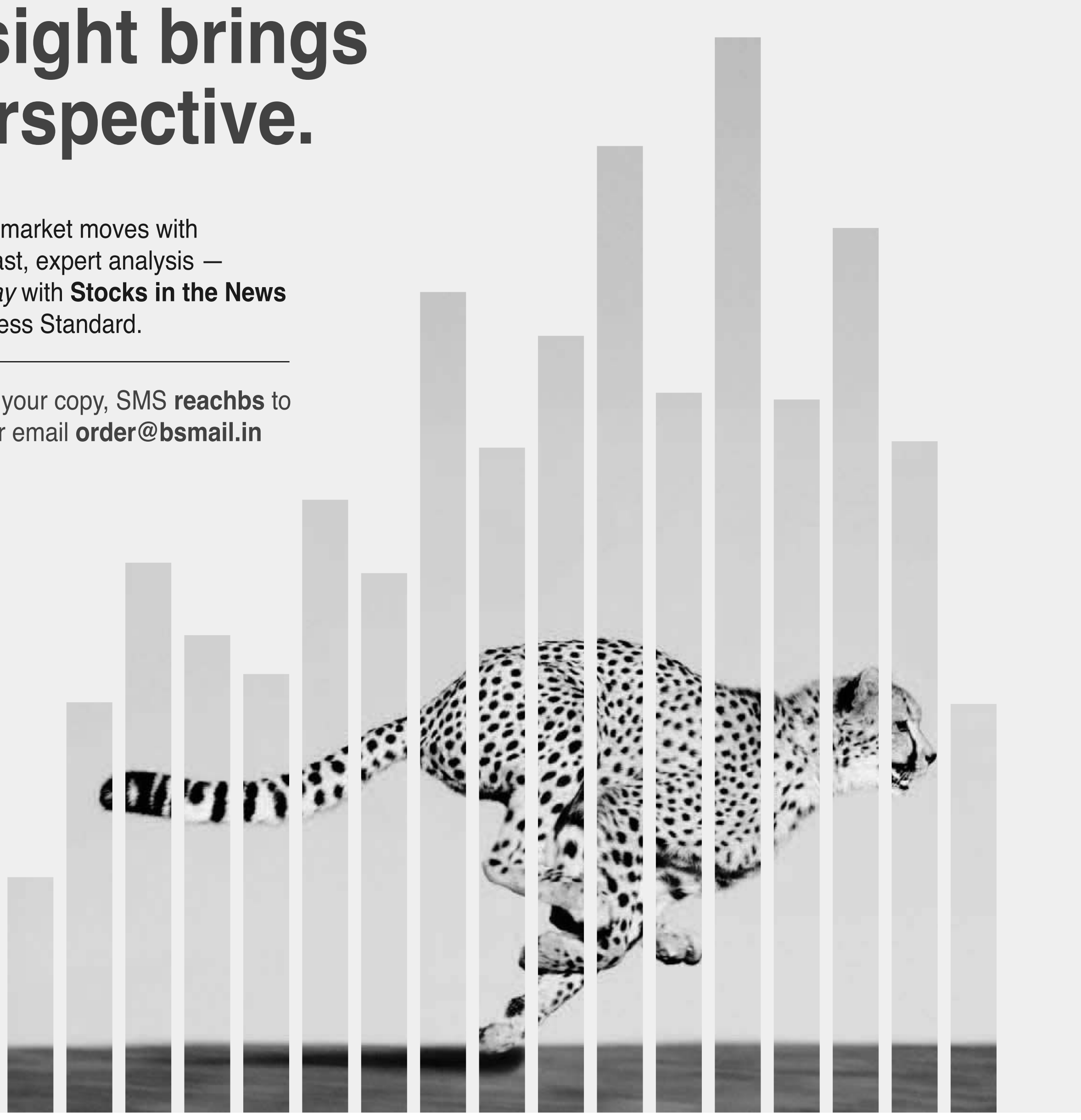

Business Standard
Insight Out

businessstandard bsindia business-standard.com

प्रपत्र सं. 14
[विनियम 33(2) देखें]
पंजीकृत ए/डी, दस्ती द्वारा, अन्यथा प्रकाशन द्वारा

कार्यालय- वसूली अधिकारी I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)
पहली मंज़िल, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स अबिड्स हैदराबाद – 500001

मांग नोटिस

ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस

आर.सी./274/2024 12-08-2026

भारतीय स्टेट बैंक

बनाम

ई सुधीर रेड्डी एवं अन्य

प्रति

(CD 1) E Sudhir Reddy E Sudhir Reddy
E Yella Reddy, M 22 3rt Vijaynagar Colony Hyderabad

(CD 2) Absorption Aircon Engineers Pvt. Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 3) Agaram Developer Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 4) Annupampattu Developers Pvt. Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 5) Hindustan Dorr-Oliver Limited
Under Liquidation Rep. By Its Liquidator (Nclt), Dorr Oliver House, Chakala, Andheri East, Mumbai-400099

(CD 6) Bibinagar Developers Pvt. Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 7) Duvvada Developerse Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 8) Dayyamarkham (India) Pvt. Limited
Rep. By Its Authorised Signatory, Mr. Sethuraman Balaji, Dorr Oliver House, Chakala, Andheri East, Mumbai-400099

(CD 9) Hdo Technologies Limited
Under Liquidation Rep. By Its Liquidator, Dorr Oliver House, Chakala, Andheri East, Mumbai-400099

(CD 10) Geo Prime Developers Pvt. Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 11) Geo Ivrcl Engineering Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 12) Gajuwaka Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 13) First Stp Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji, No. 30a, South Phase, 6th Cross Road, Thiru V. Ka Industrial Estate, Guindy, Tamilnadu-600032

(CD 14) Eragam Finlease Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Ch. Srikanth, Flat No. 305, Krise Harden, Begumpet, Hyderabad-500016

(CD 15) Eluru Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 16) Chodavaram Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 17) Ivr Prime Developers (Tuni) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 18) Ivr Prime Developers (Amlapuram) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 19) Ilavampedu Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir, M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 20) Ivr Prime Developers (Aruku) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 21) Ivr Enviro Projects Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 22) Ivr Prime Developers (Erode) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 23) Ivr Prime Developers (Red Hills) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 24) Ivr Prime Developers (Guntur) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 25) Ivr Prime Developers (Guindy) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 26) Ivr Prime Developers (Bobbili) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 27) Ivr Prime Developers (Egmore) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 28) Ivr Prime Developers (Bhimavaram) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 29) Ivr Prime Developers (Adayar) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 30) Ivr Prime Developers (Tambaram) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 31) Ivr Prime Developers (Palakkad) Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 32) Ivrcl Multilevel Car Parking Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 33) Ivrcl Megamalls Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 34) Ivrcl Gundugolanu Rajahmundry Toll Ways Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 35) Ivrcl Solar Energy Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 36) Ivrcl Raipur Bilaspur Toll Ways Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 37) Ivrcl Psc Pipes Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 38) Ivrcl Patiala Bhatinda Toll Ways Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 39) Ivrcl Narnaul Bhivani Toll Ways Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 40) Ivrcl Patalgana Trucks Terminals Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 41) Ivrcl Indore Gujarat Toll Ways Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 42) Ivrcl Goa Toll Ways Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 43) Ivrcl Clubs Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 44) Ivr Vanaprasta Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 45) Ivr Pudl Resorts And Clubs Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Panchavati Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 46) Ivrcl Tlt Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 47) Mummidi Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 48) Theata Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 49) Tirumani Signatory Private Ltd
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 50) Vedurwada Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 51) Siripuram Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 52) Simhachalam Prime Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 53) Samatteri Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji, M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 54) Rudravaram Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 55) S.V. Equities Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Ch. Srikanth, M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 56) Palladium Infrastructure &Amp; Projects Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Ch. Srikanth, Mihir, 8-2-348, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 57) INDUS Palms Hotels &Amp; Resorts Limited
Rep. By Its Authorised Signatory / Corporate Office 8-2-350/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 58) Kalyug Developers Pvt. Ltd.
Rep. By Its Authorised Signatory Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 59) Ivr Hotels & Amp; Resorts Ltd.
Rep. By Its Authorised Signatory Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 60) Soma Hotels & Amp; Resorts Ltd.
Rep. By Its Authorised Signatory Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 61) Rihim Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 62) Kunnam Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 63) Kasubugga Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 64) Vijaywada Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuramanan Balaji Mihir, 8-2-350/5/A/24/1b, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034

(CD 65) Ivr Steel Construction &Amp; Service Ltd.
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 66) Pappankuzhi Developers Pvt. Ltd.
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 67) M M Kuppam Developers Private Limited
Rep. By Its Authorised Signatory Mr. Sethuraman Balaji M-22/3rt, Vijayanagar Colony, Hyderabad-500057

(CD 68) Gamaa Developers Private Ltd.
Rep. By Its Authorised Signatory At 8-608-1/6, Naim Chambers, Beside Often Coffee Shop, Road No 10, Banjara Hills, Hyderabad-500034

सूचित किया जाता है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2) के माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद सं. OA/395/2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध ₹ 975,31,41,801 (केवल ₹ नौ सौ पचहत्तर करोड़ इकतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ एक रुपये मात्र) की राशि देय हो गई है। उक्त राशि के साथ, दिनांक 06/05/2019 से वसूली की तारीख तक लंबित एवं 0% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर भविष्य के ब्याज सहित तथा ₹ 3,80,000 (तीन लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) (संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग/पूर्ण/सीमित रूप से) की लागत भी देय है।

2. आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर यह वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।
3. आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तिथि से पहले या सुनवाई की तिथि को अपनी समस्त आस्तियों का विवरण शपथ-पत्र (हलफनामा) पर घोषित करें।
4. आपको आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 16/09/2026 को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. पूर्वोक्त राशि के अलावा आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) ऐसी ब्याज राशि, जो प्रमाणपत्र/ निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के पश्चात की अवधि के लिए देय हो;
(ख) देय राशि की वसूली के लिए यह नोटिस, वारंट जारी करने के संबंध में हुए खर्च तथा अन्य प्रक्रियाओं एवं वसूली कार्यवाहियों की समस्त लागत, शुल्क एवं व्यय।

यह आदेश दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर के साथ जारी किया गया।

वसूली अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण, हैदराबाद (डीआरटी 2)

प्रतिलिपि: (सीएच-1) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट शाखा-1, सिकंदराबाद प्रभाग डी. नं. 6-2-915, 5वीं मंज़िल, रियर ब्लॉक, बीएमडब्ल्यूएसएसबी (BMWSSB) परिसर, खैरताबाद
(सीएच-2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक
प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई - 400005
क्षेत्रीय कार्यालय: गोल्डन एडिफिस, द्वितीय मंजिल, 6-3-639/640, राजभवन रोड, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद – 500004

आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रमाणपत्र में उल्लिखित कर्जदार (कर्जदारों) से इस मामले में देय कोई भी भुगतान किया जाता है तो उसे सभी कर्जों के समेकित खाते में क्रेडिट किया जाए और भुगतान की स्थिति से वसूली अधिकारी को नियमित रूप से अवगत कराया जाए।

यह समेकित खाता वसूली अधिकारी के सत्यापन के अध्यधीन रहेगा। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस मामले के संबंध में कुल दावे का अद्यतन विवरण तथा उस संपत्ति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें, जिससे कर्ज की वसूली की जानी है।

टिप्पणी: जो लागू न हो, उसे काट दें।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

ENS ENTERPRISES LIMITED

CIN: U74120UP2016PLC075577

(Please scan this QR Code to view the Prospectus and the Abridged Prospectus)

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of "ENS Enterprises Private Limited" on January 07, 2016 under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Kanpur. Pursuant to the resolution passed by the shareholders at Extra-Ordinary General Meeting held on May 05, 2025, the Company was converted into a Public Limited Company, and its name was changed from "ENS Enterprises Private Limited" to "ENS Enterprises Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent to the conversion was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, dated May 08, 2025.The CIN of our Company is U74120UP2016PLC075577. For details of incorporation, change of registered office of our Company, please refer to the section title "History and Corporate Structure" on page no. 156 of this Prospectus.

Registered Office: B-16, 2nd Floor, Sector – 63, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh – 201301
Telephone: +91-92179 95892; **Website:** www.ens.enterprises; **E-mail:** cs@ens.enterprises
Contact person: Mr. Akhil Jain, **Company Secretary and Compliance Officer**

OUR PROMOTERS: MR. MANISH KUMAR SRIVASTAVA, MR. AVINASH KUMAR SINGH AND MR. ANUPAM KUMAR SRIVASTAVA

The Issue is being made in accordance with Regulation 229(2) of Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations and the equity shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 36,02,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF ENS ENTERPRISES LIMITED FOR CASH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 92/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 82/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO LAKHS COMPRISING OF FRESH ISSUE OF UP TO 36,02,400 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 3,314.21 LAKHS ("FRESH ISSUE") ("THE ISSUE") AND UPTO 1,81,200 EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 92/- PER SHARE AGGREGATING TO ₹ 166.70/- LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UP TO 34,21,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 92/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 3147.50/- LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.17% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 222 OF THIS PROSPECTUS.

PROPOSED LISTING

The Equity Shares offered through the Red-Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**"). Our Company has received in-principle approval vide letter LO/SME-IPO/JB/IP/719/2025-26 dated February 25, 2026 from BSE for listing of the Equity Shares. For the purposes of this Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange. The trading is proposed to be commenced on Friday, August 21, 2026 (Subject to receipt of listing and trading approvals from BSE).

BID/ISSUE PROGRAMME:	ANCHOR INVESTOR PORTION: THURSDAY, AUGUST 13, 2026	BID/ISSUE OPENED ON: FRIDAY, AUGUST 14, 2026	BID/ISSUE CLOSED ON: TUESDAY, AUGUST 18, 2026

RISK TO INVESTORS

1. Substantial portion of our revenues has been dependent on few customers. Further we do not have any long-term commitments from customers and any failure to continue our existing arrangements or loss of any one or more of our major clients would adversely affect our business and results of operations.
2. There have been certain instances of Delays in Filing with Registrar of Companies, non-filing, or partial compliance with the requirements of certain statutory authorities and applicable regulatory provisions.
3. There are outstanding litigation proceedings involving our Company, our Promoters, an adverse outcome in which, may have an adverse impact on our reputation, business, financial condition, results of operations and cash flows.
4. There are certain instances of delays in payment of statutory dues. Any delay in payment of statutory dues or non-payment of statutory dues in dispute may attract financial penalties from the respective government authorities, which may have an adverse impact on our financial condition and cash flows.
5. We have experienced negative cash flows and any negative cash flows in the future could adversely affect our financial conditions and results of operations.

OTHER RISKS

- Average Cost of Acquisition of Equity Shares by our Promoters:

Name of the Promoter	Number of Equity Shares held	Average cost per Equity Share (Rs)
Manish Kumar Srivastava	24,94,440	0.04
Avinash Kumar Singh	24,98,126	0.04
Anupam Kumar Srivastava	24,92,595	0.04

Weighted average cost of acquisition of all shares transacted in (i) last one (1) year; (ii) last eighteen (18) months and (iii) last three (3) years preceding the date of this Prospectus

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Cap Price (₹ 92) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition*	Range of Acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)*
Last one year preceding the date of the Prospectus	Nil	Nil	Not Applicable
Last three years preceding the date of the Prospectus	65	1.42	0 - 65

Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price in the last 18 months

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor Price (i.e. ₹ 87)	Cap Price (i.e. ₹ 92)
Weighted Average Cost of Acquisition of Primary/ new issuance as per paragraph 7(a) above	65.00	1.34 times	1.42 times
Weighted Average Cost of Acquisition of Secondary transactions as per paragraph 7(b) above	N.A.	N.A.	N.A.
Weighted average cost of acquisition of primary issuances/ secondary transactions as per paragraph 7(c) above	N.A.	N.A.	N.A.

PRICE BAND: ₹87/- TO ₹92/- PER EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH.

ISSUE PRICE: ₹ 92 PER EQUITY SHARES OF PAID-UP VALUE OF ₹10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 9.2 TIMES OF THE FACE VALUE

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 (1) and 253 (2) of the SEBI ICDR Regulations 2018 and as amended, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLM may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds and 6.67% for Life Insurance Companies and Pension Funds (aggregating to 40%), subject to valid Bids being received from them at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR, 2018 and amendments thereto. States that not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹10.00 Lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors" category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and as amended. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled ***"Issue Procedure"*** on page 237 of this Prospectus.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Bid/Issue opened for Anchor portion opened and closed Thursday, August 13, 2026. The Bid/Offer opened for public on
Friday, August 14, 2026, and closed on Tuesday, August 18, 2026.

Details of Anchor Investors: The Company received 02 Anchor Investor Application Forms from 02 Anchor Investors (including Nil mutual funds through Nil Mutual Fund schemes & Nil life insurance companies and pension funds) for 10,26,000 Equity Shares. Such 02 Anchor Investors through 02 Anchor Investor Application Forms were allocated 10,26,000 Equity Shares at a price of Rs. 92/- per Equity Share under the Anchor Investor Portion, aggregating to Rs. 9,43,92,000/-

The issue was subscribed to the extent of **16.10** times (excluding the Anchor Investor Portion) as per the bid books of BSE (the "**Bid Files**") after removing multiple and duplicate bids.

After removing multiple and duplicate bids, bids (UPI Mandates) not accepted by investors / blocked, bids rejected under application banked but bid not registered and valid rejections cases from the '**Bid Book'**, the Issue was subscribed **12.23** times (excluding the Anchor Investor Portion).

The details of the break-up of rejections from the bid book under the various heads are as mentioned below:

Details of Application Received: (After Technical Rejections)

Sr. No.	Category	Gross		Less: Valid Rejections		Valid		Allotment	
		Appli cations	Equity Shares	Ap plicati ons	Equity Shares	Appli cations	Equity Shares	Appli cations	Equity Shares
1	Qualified Institutional Buyers	14	64,54,800	0	0	14	64,54,800	13	6,84,000
2	Non-Institutional Investors 1 (not more than 1,000,000/-)	638	26,13,600	13	48,000	625	25,65,600	47	1,71,600
3	Non-Institutional Investors 2 (More than 1,000,000/-)	726	92,64,000	7	87,600	719	91,76,400	95	3,42,000
4	Market Maker	1	1,81,200	0	0	1	1,81,200	1	1,81,200
5	Individual Investors	5,532	1,32,76,800	63	1,51,200	5,469	1,31,25,600	499	11,97,600
	Total	**6,911**	**3,17,90,400**	**83**	**2,86,800**	**6,828**	**3,15,03,600**	**655**	**25,76,400**

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr.No.	Price	Bids	Shares Applied	Amount Applied
1	87.00	10	24,000	20,88,000.00
2	88.00	2	4,800	4,22,400.00
3	89.00	2	4,800	4,27,200.00
4	90.00	9	33,600	30,24,000.00
5	91.00	2	4,800	4,36,800.00
6	92.00	6,886	3,17,18,400	2,91,80,92,800.00
Total		**6,911**	**3,17,90,400**	**2,92,44,91,200.00**

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on August 19, 2026.

A. **Allocation to Individual Investors (After Technical Rejections) (including ASBA applications): The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have bid at the Cut-Off Price or at the** Issue Price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with the BSE. This category has been subscribed to the extent of 10.96 times. The total number of Equity Shares Allotted in Individual Investor Portion is 1197600 Equity Shares to 499 successful Individual Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants		Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(13)
							Before rounding off	After rounding off							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	2400	5469	100.00	13125600	100.00	1197600	219	2400	499	5469	499	100.00	1197600	100.00	0
	Grand Total	**5469**	**100.00**	**13125600**	**100.00**	**1197600**	**219**	**2400**			**499**	**100.00**	**1197600**	**100.00**	**0**

B. **Allocation to Non-Institutional Investors up to Rs. 10,00,000 (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Individual Investor** upto Rs. 10,00,000, who have bid at the Issue Price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 14.95 times (after rejections). The total number of Equity Shares allotted in this category is 171600 Equity Shares to 47 successful to Individual Investor upto Rs. 10,00,000. The category-wise details of the Basis of Allotment is as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant		Ratio of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
							Before rounding off	After rounding off								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	3600	529	84.64	1904400	74.2282507	145242.24	274.56	3600	40	529		40	85.106383	144000	83.91608392	-1242.24
2	4800	50	8.00	240000	9.35453695	13728	274.56	3600	2	25		4	8.5106383	14400	8.391608392	672
3	6000	4	0.64	24000	0.935453695	1098.24	274.56	3600	0	4		0	0	0	0	-1098.24
4	7200	11	1.76	79200	3.086997194	3020.16	274.56	3600	1	11		1	2.12765957	3600	2.097902098	579.84
5	8400	4	0.64	33600	1.309635173	1098.24	274.56	3600	0	4		0	0	0	0	-1098.24
6	9600	6	0.96	57600	2.245088868	1647.36	274.56	3600	0	6		0	0	0	0	-1647.36
7	10800	21	3.36	226800	8.840037418	5765.76	274.56	3600	2	21		2	4.25531915	7200	4.195804196	1434.24
8			Serial No 2,4,7 shall be allocated 2400 shares to the Allottees					1200	2	7		0	0	2400	1.398601399	2400
Total		**625**	**100.00**	**2565600**	**100.00**	**171600**						**47**	**100.00**	**171600**	**100.00**	**0**

....continue to next page

भारत-जापान के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता

भारत-जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिका तथा ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी पर भी चर्चा

बीएस संवाददाता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी से द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-जापान की रणनीतिक साझेदारी और खास तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसमें व्यावहारिक स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

नई दिल्ली में बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत और जापान अपनी नौसेनाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसमें समुद्री क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान, समुद्र में स्थिति पर नजर रखने की क्षमता बढ़ाना और समुद्र में खोज एवं बचाव अभियान जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष बलों के बीच भी संपर्क और आदान-प्रदान बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों मंत्रियों ने भविष्य में भारत में संयुक्त सैन्य कमान स्थापित होने के बाद जापान के साथ इन कमान के स्तर पर भी सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत में संयुक्त कमान बनाने की योजना को अभी सुरक्षा से जुड़ी मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी मिलना बाकी है। भारत के हिंद महासागर में रणनीतिक हितों को देखते हुए देश में एक समुद्री संयुक्त कमान बनाए जाने की उम्मीद है।

दोनों देश समुद्री व्यापार और संचार के महत्त्वपूर्ण रास्तों की सुरक्षा के लिए भी बेहतर तालमेल बनाएंगे। इसके लिए नौसैनिक जहाजों की एक-दूसरे के देशों में यात्राएं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्यकर्मियों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा बंदरगाहों और रखरखाव एवं मरम्मत सुविधाओं के इस्तेमाल जैसे लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ाया जाएगा।

दोनों रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि इससे भारत और जापान की रणनीतिक और परिचालन से जुड़ी जरूरतें पूरी हो सकें। भारत और जापान समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाएंगे। इसके साथ ही दोनों देश नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन की संभावनाएं भी तलाशेंगे। इसमें जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने एक कार्यशील समूह बनाने पर भी चर्चा की। यह समूह सैन्य अभियानों, खुफिया जानकारी, रक्षा उपकरण, तकनीक और रक्षा उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में एकीकृत तरीके से सहयोग को आगे बढ़ाने पर काम करेगा। इसमें दोनों देशों की अपनी-अपनी नीतियों और संप्रभु फैसलों का पूरा सम्मान किया जाएगा। दोनों मंत्रियों ने भारत और जापान की सरकारों तथा सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का स्वागत किया। दोनों देश 'जापान-भारत के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत करने के लिए सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित बैठक के दौरान जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत-जापान संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की थी।

भारत और जापान के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के सदस्य हैं। यह चार देशों का समूह वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के कुछ समय बाद औपचारिक रूप से बनाया गया था। हालांकि, क्वाड की 2024 के बाद से कोई शिखर बैठक नहीं हुई है लेकिन इस साल की शुरुआत में इस समूह ने समुद्री सहयोग से जुड़े एक समझौते की घोषणा की थी।

कुछ समय तक क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना माना जाता रहा। हालांकि, क्वाड की उपयोगिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं खासतौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका का ध्यान एशिया से कुछ हद तक हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग लगातार जारी है।

गुरुवार को हुई भारत-जापान द्विपक्षीय बैठक में राजनाथ सिंह और कोइजुमी ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने बढ़ते वैश्विक तनाव, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिका तथा ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी से पैदा हुई स्थिति पर अपने आकलन साझा किए। इन घटनाओं के कारण वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और कई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा था कि वह जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की घोषणा करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि इस संकरे समुद्री मार्ग के महत्त्वपूर्ण हिस्सों पर उसका नियंत्रण है। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने ऐसी किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जिससे समुद्र और हवाई क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रभावित होती हो। दोनों देशों ने बल या दबाव के जरिए मौजूदा स्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश का भी विरोध किया। भारत और जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक इस साल के अंत में जापान की राजधानी टोक्यो में होने की उम्मीद है।

...in continuation of previous page

C. Allocation to Non-Institutional Investors above Rs. 10,00,000 (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Institutional Investors above Rs. 10,00,000, who have bid at the Issue Price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 26.83 times (after rejections). The total number of Equity Shares allotted in this category is 3,42,000 Equity Shares to 95 successful Institutional Investors above Rs. 10,00,000. The category-wise details of the Basis of Allotment is as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	12000	686	95.41	8232000	89.70838237	326303.1989	475.6606398	3600	13	98		91	95.78947368	327600	95.78947368	1296.801113
2	14400	1	0.14	14400	0.156924284	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
3	15600	8	1.11	124800	1.360010462	3805.285118	475.6606398	3600	1	8		1	1.052631579	3600	1.052631579	-205.2851182
4	18000	1	0.14	18000	0.196155355	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
5	19200	1	0.14	19200	0.209232379	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
6	21600	2	0.28	43200	0.470772852	951.3212796	475.6606398	3600	0	2		0	0	0	0	-951.3212796
7	24000	4	0.56	96000	1.046161894	1902.642559	475.6606398	3600	1	4		1	1.052631579	3600	1.052631579	1697.357441
8	26400	5	0.70	132000	1.438472604	2378.303199	475.6606398	3600	1	5		1	1.052631579	3600	1.052631579	1221.696801
9	31200	1	0.14	31200	0.340002615	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
10	32400	1	0.14	32400	0.353079639	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
11	33600	1	0.14	33600	0.366156663	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
12	34800	1	0.14	34800	0.379233686	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
13	36000	1	0.14	36000	0.39231071	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
14	37200	1	0.14	37200	0.405387734	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
15	49200	1	0.14	49200	0.53615797	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
16	54000	2	0.28	108000	1.17693213	951.3212796	475.6606398	3600	0	2		0	0	0	0	-951.3212796
17	55200	1	0.14	55200	0.601543089	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
18	79200	1	0.14	79200	0.863083562	475.6606398	475.6606398	3600	0	1		0	0	0	0	-475.6606398
			3600 Shares Shall be allocated to Serial No,2,4,5,6 and 9 to 18 to unsuccessful Allottee					3600	1	16		1	1.052631579	3600	1.052631579	3600
	Grand Total	**719**	**100.00**	**9176400**	**100.00**	**342000**						**95**	**100.00**	**342000**	**100.00**	**0**

D. Allotment to QIBs (after rejections): Allotment to QIBs, who have Bid at the Issue Price of Rs. 92 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with the BSE. This category has been subscribed to the extent of 9.44 times of QIB Portion. The total number of Equity Shares Allotted in the QIB Portion is 6,84,000 Equity Shares which were allotted to 13 successful QIB Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	4,800	1	7.14	4,800	0.07	509	509	3,600	0	1		0	0.00	0	0.00	-509
2	22,800	1	7.14	22,800	0.35	2,416	2,416	3,600	1	1		1	7.69	3,600	0.53	1,184
3	42,000	1	7.14	42,000	0.65	4,451	4,451	4,800	1	1		1	7.69	4,800	0.70	349
4	55,200	1	7.14	55,200	0.86	5,849	5,849	6,000	1	1		1	7.69	6,000	0.88	151
5	1,60,800	1	7.14	1,60,800	2.49	17,040	17,040	16,800	1	1		1	7.69	16,800	2.46	-240
6	1,68,000	1	7.14	1,68,000	2.60	17,803	17,803	18,000	1	1		1	7.69	18,000	2.63	197
7	2,86,800	1	7.14	2,86,800	4.44	30,392	30,392	30,000	1	1		1	7.69	30,000	4.39	-392
8	3,00,000	1	7.14	3,00,000	4.65	31,790	31,790	31,200	1	1		1	7.69	31,200	4.56	-590
9	3,25,200	1	7.14	3,25,200	5.04	34,461	34,461	34,800	1	1		1	7.69	34,800	5.09	339
10	3,31,200	1	7.14	3,31,200	5.13	35,096	35,096	34,800	1	1		1	7.69	34,800	5.09	-296
11	3,52,800	1	7.14	3,52,800	5.47	37,385	37,385	37,200	1	1		1	7.69	37,200	5.44	-185
12	3,80,400	1	7.14	3,80,400	5.89	40,310	40,310	40,800	1	1		1	7.69	40,800	5.96	490
13	16,29,600	1	7.14	16,29,600	25.25	1,72,685	1,72,685	1,72,800	1	1		1	7.69	1,72,800	25.26	115
14	23,95,200	1	7.14	23,95,200	37.11	2,53,814	2,53,814	2,53,200	1	1		1	7.69	2,53,200	37.02	-614
	Grand Total	**14**	**100.00**	**64,54,800**	**100.00**	**6,84,000**						**13**	**100.00**	**6,84,000**	**100.00**	**0**

E. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of Rs. 92 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category 1,81,200 Equity Shares to 01 successful applicant.

Sr. No.	No. of Shares applied for (Category Wise)	Number of applications received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of allottees to applicants		Serial Number of Qualifying applicants	Number of Successful applicants (after rounding off)	% to Total	Total No. of Shares allocated/ allotted	% to Total	Surplus/ Deficit (7)-(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	1,81,200	1	100.00	1,81,200	100.00	1,81,200	1,81,200	1,81,200	1	1		1	100.00	1,81,200	100.00	0
	Grand Total	**1**	**100.00**	**1,81,200**	**100.00**	**1,81,200**	**1,81,200**	**1,81,200**				**1**	**100.00**	**1,81,200**	**100.00**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 19, 2026 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange and has authorized the corporate action for the transfer of the Equity Shares to various successful applicants.

The refund / allotment intimation will be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories on or about August 20, 2026. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to August 20, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact Registrar at the address given below.

The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on BSE within three working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated August 19, 2026 (**"Prospectus"**).

The Book Running Lead Manager associated with the Issue have handled 12 SME public issues and NIL Main Board Public Issues during the current financial year and three financial years preceding the current Financial Year as described below:

Type	FY 2026-27	FY 2025-26	FY 2024-25	Total
SME IPO	5	6	1	12
MAIN Board IPO	-	-	-	-
TOTAL	5	6	1	12
STATUS UPTO AUGUST 20, 2026	5	6	1	12

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Abhipra Capital Limited at www.abhipra.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

ABHIPRA CAPITAL LIMITED
GF 58-59, World Trade Center, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi - 110001, **Telephone:** +91-11-42390799, **Email ID:** cs@abhipra.com
Investor Grievance Email: grievance@abhipra.com, **Website:** www.abhipra.com
Contact Person: Mr. Kapil Bansal
SEBI Registration Number: INR000003829, **CIN:** U74899DL1994PLC061802

For **ENS Enterprises Limited**
On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Manish Kumar Srivastava
Whole Time Director & CFO

Place: Noida
Date: August 20, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ENS ENTERPRISES LIMITED.

ENS Enterprises Limited has filed the Prospectus with RoC and the SEBI on August 19, 2026. The Prospectus is expected to be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com, respectively, the website of the Company at www.ens.enterprises and on the websites of the Book Running Lead Manager **("BRLM")**, i.e. Corporate Makers Capital Limited at www.corporatemakers.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see ***"Risk Factors"*** beginning on page 25 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the Prospectus filed with SEBI and the Stock Exchanges, and should instead rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved, for making any investment decision. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended **("U.S. Securities Act")** or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) in the United States solely to "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act and (b) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation of the U.S. Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made.

'उद्योग परीक्षण' का पुराना ढांचा बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने पुराने मामलों के लिए दी यह व्यवस्था, नई संहिता के तहत आगे तय होगी परिभाषा

भाविनी मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उसके द्वारा लगभग 50 साल पुराने 'बेंगलूरु जलापूर्ति' फैसले में 'उद्योग' की दी गई व्याख्या नई औद्योगिक संबंध संहिता (आईआरसी) 2020 के तहत आने वाले विवादों पर स्वतः लागू नहीं होगी।

इस फैसले से पुराने और नए श्रम विवादों के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित हो गया है। 1978 के फैसले ने उद्योग की परिभाषा का दायरा काफी व्यापक रखा था लेकिन अब अदालत ने यह व्यवस्था दी है कि यह तय करने के लिए एक नया ढांचा विकसित किया जा सकता है कि कोई गतिविधि या प्रतिष्ठान 'उद्योग 'की श्रेणी में आता है या नहीं। इसके लिए 1978 में तय किए गए परीक्षण को स्वतः लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत पैदा होने वाले मामलों का फैसला आगे भी 1978 में तय किए गए व्यापक परीक्षण के आधार पर ही किया जाता रहेगा। लेकिन नई संहिता के तहत उद्योग की परिभाषा की व्याख्या अदालतों को स्वतंत्र रूप से करनी होगी। पुराने फैसले को इस व्याख्या का स्वतः आधार नहीं माना जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले के कई पहलुओं पर विभाजित फैसला दिया। पीठ के सामने मुख्य सवाल 1947 के अधिनियम की धारा 2(जे) के तहत उद्योग शब्द के अर्थ का था। बेंगलूरु जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय पीठ ने उद्योग शब्द की बहुत व्यापक व्याख्या की थी।

उस फैसले में कहा गया था कि कोई गतिविधि तभी उद्योग मानी जाएगी जब वह संगठित और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो, उसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सहयोग शामिल हो तथा वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या उपलब्धता कराती हो।

इस तिहरे परीक्षण के कारण कई तरह के प्रतिष्ठान श्रम कानूनों के दायरे में आ गए थे। इनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और नगरपालिकाएं भी शामिल

थीं। केवल प्रमुख संप्रभु कार्य जैसे न्यायपालिका, रक्षा और कानून प्रवर्तन को बाहर रखा गया था। नई आईआरसी जो नवंबर 2025 में लागू हुई वह धारा 2(पी) के तहत उद्योग को परिभाषित करती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में बहुमत ने माना कि धारा 2(जे) की व्याख्या को धारा 2(पी) की व्याख्या का आधार नहीं माना जा सकता। इसमें न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, आलोक अराधे और विपुल एम. पंचोली शामिल थे। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची ने इस पहलू पर बहुमत से सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'आईआरसी की धारा 2(पी) में 'उद्योग' का भविष्य धारा 2(जे) की व्याख्या से बोझिल नहीं है।' यद्यपि यह निर्णय पुराने कानून के तहत लंबित या निष्पादित मामलों को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने कहा कि 1947 अधिनियम के तहत अदालतों, न्यायाधिकरणों और श्रम प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही बेंगलूरु जलापूर्ति निर्णय के अनुसार ही तय की जानी चाहिए। देश की अग्रणी लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास के विवाद मामलों के प्रमुख इंद्रनील देशमुख ने कहा, 'लंबित मामले, पूर्व पुरस्कार और निष्पादित समझौते 1978 परीक्षण द्वारा शासित रहेंगे। वास्तविक परिणाम भविष्य के लिए है क्योंकि अदालत ने कहा है कि 1978 का निर्णय नई संहिता के लिए व्यापक आधार नहीं माना जाएगा। नियोक्ताओं को इसलिए कोड के तहत एक नई शुरुआत मिलती है जबकि श्रमिकों को पहले से प्राप्त सुरक्षा बनी रहती है।' देशमुख ने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणियां मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं क्योंकि पूर्ण निर्णय और राय अभी प्रतीक्षित हैं। उन्होंने कहा कि धारा 2(जे) के तहत उद्योग एक परिभाषित वैधानिक अभिव्यक्ति थी न कि केवल सामान्य शाब्दिक अर्थ। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक विशिष्ट कानूनी अर्थ दिया था और यही कारण है कि शब्दकोश में दी गई परिभाषाएं कभी निर्णायक नहीं रही थीं।

ऋषभ गांधी ऐंड ऐसोसिएट्स के संस्थापक ऋषभ गांधी ने कहा, 'निर्णय का तात्कालिक प्रभाव सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है। 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाहियां बेंगलूरु जलापूर्ति में निर्धारित व्यापक परीक्षण द्वारा शासित होती रहेंगी। नियोक्ता इस निर्णय का उपयोग निष्पादित मामलों को फिर से खोलने या पुराने कानून के तहत लंबित विवादों में देयता से बचने के लिए नहीं कर सकते।'

उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, परोपकारी निकायों और सरकारी संस्थाओं के लिए प्रासंगिक है जिनकी उद्योग के रूप में स्थिति अक्सर विवादित रही है। गांधी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आईआरसी के तहत 'उद्योग' की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। 1947 अधिनियम के तहत विकसित व्यापक व्याख्या को स्वतः नई संहिता में नहीं लाया जा सकता।

झारखंड में नियुक्तियां रद्द करने पर अदालत की रोक

एजेंसियां

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं तक के माध्यम से नियुक्त किए गए सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित अधिसूचनाओं पर गुरुवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने से संबंधित अधिसूचना के अमल पर भी रोक लगा दी।

सरकारी अधिसूचनाओं के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं के वकील अमृतांश वत्स ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आरंभिक तौर पर 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तक के जरिए हुई नियुक्तियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने से जुड़ी अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है। वत्स के अनुसार न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले पर रोक लगायी जाती है। वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से लगभग 450 उम्मीदवारों को राहत मिली है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित 54 उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय के आदेश से राहत मिली। ये लोग अपनी परीक्षा रद्द होने के बाद नतीजों का इंतज़ार कर रहे थे। इस आदेश के बाद राज्य सचिवालय के बाहर राहत और जश्न का माहौल देखा गया। गुमला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात आशा राज ने बताया कि सरकार द्वारा रद्द की गई 22 परीक्षाओं में उनकी परीक्षा भी शामिल थी।

नीटः पुलिस कार्रवाई की जांच को समिति

नई दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने समिति गठित कर दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना के पीठ ने कहा कि इस समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एलआर बिश्नोई भी शामिल हैं। समिति से कहा गया है कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल समेत अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच करे।

बांग्लादेश के पीएम की भारत यात्रा पर संशय

भाषा

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अगले महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत यात्रा पर जाने की संभावना बहुत कम है। विदेश मामलों के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकार हुमायूं कबीर ने यह बात कही। कबीर ने कहा कि जब तक आपसी विश्वास पर आधारित उचित माहौल तैयार नहीं किया जाता और नई दिल्ली की ओर से सम्मानजनक निमंत्रण नहीं दिया जाता, तब तक प्रधानमंत्री रहमान के भारत दौरे की संभावना काफी कम है।

उन्होंने कहा कि ढाका स्पष्ट रूप से तय किए गए राष्ट्रीय हितों के बिना उच्च-स्तरीय यात्रा आयोजित करने की कोई जल्दबाजी में नहीं है। कबीर ने एक साक्षात्कार में सरकारी समाचार एजेंसी 'बीएसएस' से कहा, 'राष्ट्रीय हितों से समझौता करके या उनसे आगे बढ़कर उच्च-स्तरीय यात्रा के लिए जल्दबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है।'

यह साक्षात्कार 17 अगस्त को लिया गया था और गुरुवार को प्रकाशित हुआ। इन टिप्पणियों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान की 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

तारिक रहमान, पीएम, बांग्लादेश

के लिए नई दिल्ली यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

आलमगीर नए राष्ट्रपति

बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर गुरुवार को देश के नये राष्ट्रपति चुने गए। देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने कहा कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हरा दिया।

एआई से एसएमबी को विज्ञापनों में मिली मदद

उदिशा श्रीवास्तव

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) विभिन्न कारोबारों को लागत के बोझ, जटिलता और सीमित संसाधनों जैसी पारंपरिक बाधाओं से निजात पाकर विज्ञापनों को कहीं अधिक बेहतर और सुलभ बनाने में मदद कर रहा है।

एमेजॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10 में से 9 (87 प्रतिशत) लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय (एसएमबी) कहते हैं कि एआई संचालित विज्ञापन उपकरणों ने उन्हें उन विज्ञापन चैनलों, दर्शकों या प्रारूपों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर लगते थे। इनमें स्ट्रीमिंग टीवी जैसे उच्च-प्रभाव वाले वीडियो प्रारूप भी शामिल हैं। पहुंच में विस्तार के अलावा एआई व्यवसायों को बढ़ने में भी मदद कर रहा है। 75 फीसदी का कहना है कि एआई सक्षम विज्ञापन ने व्यवसाय वृद्धि का समर्थन किया है और 68 प्रतिशत का कहना है कि सरल उपकरणों के कारण उनके विज्ञापन में अधिक रचनात्मकता खुली है। एमेजॉन ऐड्स द्वारा तैयार और ओपनियम द्वारा संचालित इस रिपोर्ट में 7 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक के आंकड़े शामिल हैं। एआई प्रयोग की लागत को कम कर रहा है और एसएमबी को तेज

प्रतिक्रिया प्रदान कर रहा है, जिससे वे विस्तार या नई उत्पाद श्रृंखलाएं लॉन्च जैसी विकास रणनीतियों को अपनाने में सक्षम हो रहे हैं। तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) का कहना है कि एआई सक्षम विज्ञापन गतिविधि या रणनीति ने व्यवसाय वृद्धि का समर्थन किया है, 59 प्रतिशत का कहना है कि इसने उन्हें नए देशों में विस्तार करने में मदद की है और 58 प्रतिशत का कहना है कि इसने उन्हें नई उत्पाद श्रेणियां शुरू करने की क्षमता दी है।

नए चैनलों तक पहुंच और वैश्विक विस्तार की क्षमता से परे एसएमबी अभियान वितरण में भी व्यावहारिक लाभ देखते हैं। 65 प्रतिशत का कहना है कि एआई तेज अनुकूलन सक्षम करता है, 62 प्रतिशत का कहना है कि यह उन्हें ग्राहकों को जल्दी खोजने में मदद करता है।

मुफ्त पेशकश से बदल जाएगा कोचिंग बाजार

छोटे और मझोले कोचिंग केंद्रों को अस्तित्व बचाने के लिए करना होगा संघर्ष

अहोना मुखर्जी

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए केंद्र सरकार का प्रस्तावित मुफ्त कोचिंग नेटवर्क देश के कोचिंग बाजार को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इससे जहां छोटे और मझोले निजी कोचिंग केंद्रों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ेगा वहीं ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा छात्रों का जोर रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव निजी कोचिंग बाजार, विशेष रूप से छोटे और मझोले प्रदाताओं पर दबाव डाल सकता है, जबकि स्थापित संस्थान व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करके अपनी मांग बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं।' मुफ्त कोचिंग परीक्षाओं की तैयारी में लागत की बाधा को जरूर तोड़ सकती है लेकिन इसमें यह गारंटी नहीं होगी कि सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम पढ़ाने से सफलता भी समान रूप से मिल पाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि उपकरणों, कनेक्टिविटी, भाषा दक्षता, शैक्षणिक नींव और तैयारी के लिए उपलब्ध समय में अंतर का असर सफलता के परिणामों पर दिखेगा।

एसोसिएशन ऑफ इंटरनैशनल स्कूल्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद सुल्तान अहमद ने कहा, 'संसाधनों तक पहुंच और अवसर दोनों एक चीज नहीं हैं।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि मुफ्त कोचिंग का लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाना है तो इसके लिए बहुभाषी सामग्री, ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया, परामर्श, डाउट सॉल्विंग यानी छात्रों के मन में उठने वाले सवालों का समाधान और ऑफलाइन सुविधाएं भी देनी होंगी। टीमलीज एडटेक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू रूज ने भी कहा कि

छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी के दौरान विभिन्न स्तरों पर पर समस्याओं के समाधान की सुविधा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, परामर्श और दूरदराज के छात्रों तक ऑनलाइन पढ़ाई के नेटवर्क का विस्तार करना होगा।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सरकार की ओर से प्रस्तावित मुफ्त कोचिंग का निजी कोचिंग केंद्रों पर समान रूप से असर नहीं पड़ेगा। सुल्तान अहमद कहते हैं कि यदि सरकार अच्छे शिक्षकों का प्रबंध कर लेती है, गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करा देती है और फ्री मॉक टेस्ट सुविधा दे देती है तो ऐसे हालात में छोटे और मझोले कोचिंग केंद्रों के समक्ष चुनौतीपूर्ण हालात बन जाएंगे, क्योंकि वे इन सुविधाओं के लिए शुल्क लेते हैं, लेकिन समान सेवाओं के लिए सरकार की मुफ्त पेशकश के बाद उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'यदि कोई छात्र बिना किसी शुल्क के एक अच्छा शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकता है, तो किसी मझोले कोचिंग सेंटर के लिए उसी व्याख्यान के लिए शुल्क लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा।' अहमद ने बताया कि बड़े संस्थान अपनी मांग बनाए रख सकते हैं, क्योंकि छात्र और माता-पिता संरचना, अनुशासन, व्यक्तिगत ध्यान, परामर्श और डाउट सॉल्विंग के लिए भी भुगतान करते हैं। शांतनू रूज ने भी कहा कि फौरी तौर पर कोचिंग सेंटर बंद होने या दूसरी जगह चले जाने जैसा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल कोचिंग की कीमत पर अधिक असर पड़ने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा, 'मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के मूल्य और सामग्री उपलब्ध कराने में प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले छोटे कोचिंग केंद्रों पर सबसे पहले असर पड़ सकता है, जबकि बड़े संस्थान छात्रों के साथ सीधा जुड़ाव, पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल और बेहतर परिणाम जैसी सुविधाओं से तुलना कर मोटी फीस लेने को जायज ठहरा सकते हैं।' जी ग्रुप होल्डिंग में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सेल्स) विजय वसंत ने भी यही कहा कि सरकार की प्रस्तावित मुफ्त कोचिंग का असर छोटे और मझोले कोचिंग केंद्रों पर दिखेगा, जबकि अपनी बेहतर सुविधाओं के बल पर बड़े संस्थानों की मांग बनी रहेगी। एक और खास बात यह कि कोचिंग की सुविधाएं बढ़ने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। वसंत ने तर्क दिया कि आसानी से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलने से अधिक युवाओं, विशेष रूप से छोटे शहरों के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने और एक से अधिक बार प्रयास करने का हौसला मिलेगा। इसका सीधा प्रभाव सरकारी नौकरियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के रूप में दिखेगा।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
पी.एस.बी
प्रधान कार्यालयः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
द्वितीय तल, भूखंड संख्या–151, सेक्टर–44, संस्थागत क्षेत्र,
गुरुग्राम – 122003 Email: ho.it@psb.bank.in
जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

निविदा सूचना

आईटी सुरक्षा समाधान और सेवाओं की आपूर्ति, स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए बोलीदाता के चयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध" के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विनिर्देशों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के लिए आरएफपी, बैंक वेबसाइट https://punjabandsind.bank.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।
उक्त निविदा से संबंधित आगे कोई भी संशोधन, केवल बैंक वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।
दिनांकः 19.08.2026 सहायक महाप्रबंधक–आईटी

https://bankofbaroda.bank.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

आरएफ़पी सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सुविधा प्रबंधन विभाग, मुंबई GeM पोर्टल के माध्यम से बैंक की बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई और बड़ौदा भवन (प्रधान कार्यालय), वडोदरा में मौजूदा CISCO आधारित वाई–फाई सेटअप का उन्नयन और एएमसी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है।

विवरण बैंक की वेबसाइट https://bankofbaroda.bank.in के निविदा अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

निविदा में संशोधन सहित किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पहले इसका संदर्भ लें।

ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.09.2026 को 15:00 बजे तक।

स्थानः मुंबई
तारीखः 21.08.2026
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(सु.प्र, सी.ओ.ए, सुरक्षा, पी.डी. एवं आर.डी.पी.)
74/26-27

LohiaCorp
Integrity | Quality | Value
LEADERSHIP THROUGH
INNOVATION & TECHNOLOGY

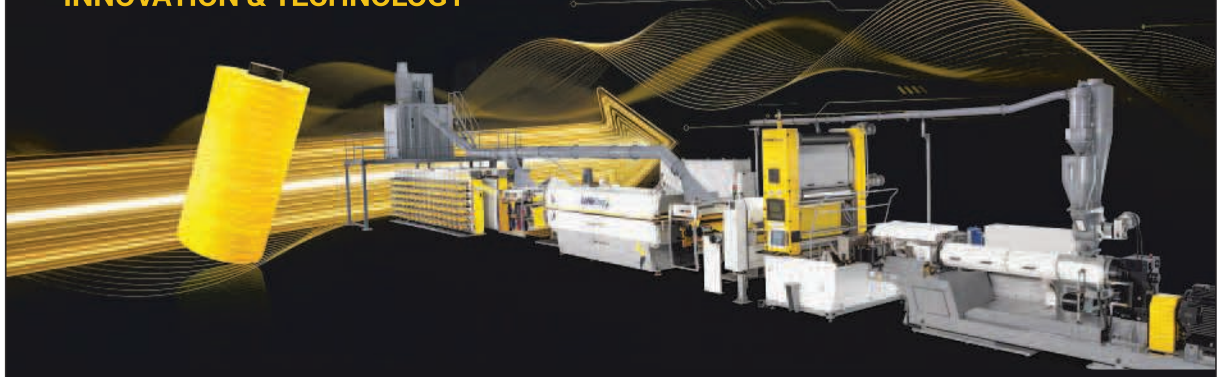

REVENUE GROWTH YoY 60%
EBITDA GROWTH YoY 168%
PAT GROWTH YoY 292%

Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter ended on June 30, 2026

(₹ in Millions)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2025 Unaudited	Year Ended 31.03.2026 Audited
1.	Total Income	5,095.80	3,190.13	17,378.70
2.	Earnings before Interest, Tax, Exceptional Items, Depreciation and amortisation (EBITDA)	1,067.38	398.85	3,394.51
3.	Profit before tax for the period/ year	912.64	234.83	2,650.39
4.	Profit for the period/ year	662.61	168.85	1,934.52
5.	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising profit for the period/ year after tax and Other Comprehensive Income (net of tax)]	676.37	173.63	1,884.78
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- Per Share)	-	-	105.65
7.	Reserves and surplus	-	-	5,109.92
8.	Earning Per Share (of Rs. 1/- each) (Not annualized except year ended)			
	- Basic and Diluted	6.27	1.60	18.31

Note: The above is an extract of the detailed Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Financial Results (consolidated and standalone) are available on the Stock Exchange websites:- www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company's website: www.lohiagroup.com. The same can also be accessed by scanning the given QR code.

Place : Kanpur
Date : August 19, 2026

For Lohia Corp Limited
Sd/-
Raj Kumar Lohia
Chairman and Managing Director
DIN: 203659

Lohia Corp Limited
CIN: U28261UP2023PLC183476
Registered Office: D-3/A, Panki Industrial Estate, Kanpur - 208 022, Uttar Pradesh, India
Corporate Office & Works: Lohia Industrial Complex, Chaubepur, Kanpur - 209 203, Uttar Pradesh, India
Ph. No.: +91-512-3536111, +91-512-3123222 | Web: www.lohiagroup.com | Email: investors@lohiagroup.com